राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 15 अंक: 85 पृष्ठ: 08

RNI : HPHIN/2012/48072

actionindiauna@gmail.com

हिमाचल संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़

RKB GROUP
Rakesh Bhardwaj Group

घर के पास पीएनजी पाइपलाइन, तो कनेक्शन लेना ही होगा, देश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच सरकार ने बुधवार को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति को सामान्य बताया है। भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और लगभग 26 करोड़ टन तेल उपलब्ध है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए, जबकि 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर चले गए और 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए। शर्मा ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इसमें कोई कमी नहीं आई है, जबकि 92 फीसदी से ज्यादा बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और बुकिंग का स्तर बढ़ने के बावजूद डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें होटल, ढाबे, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत लगभग 22 हजार टन

एलपीजी की आपूर्ति की गई है और 30 हजार छोटे सिलेंडर बांटे गए हैं। कई राज्यों में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अतिरिक्त केरोसिन (मिट्टी का तेल) का आवंटन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी 100 फीसदी कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि कई कंपनियों ने कई इंसेंटिव्स की घोषणा की है, जैसे 500 रुपये तक की फ्री गैस या सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट दी गई है। सुजाता शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। लगभग 2,700 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जबकि 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों से अपील कर रही है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और घबराएं नहीं।

स्पष्ट किया

भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं : केंद्र सरकार

आईटीआई पास युवाओं के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और रोजगार मेले शुरू करने के निर्देश

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए है कि आईटीआई से पास होने वाले प्रशिक्षुओ के शिक्षुता और प्लेसमेंट डाटा को एकत्रित कर पोर्टल बनाया जाएं। साथ ही आईटीआई से पास आउट हुए प्रशिक्षुओं का डेटा राज्य के उद्योग संस्थानों को उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल पोर्टल का निर्माण किया जाएं। साथ हर जिला में रोजगार के बड़े मेले लगाएं जाए। बकायदा इसके लिए विभाग कलेंडर भी जारी करें। ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को हरियाणा निवास में युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग हरियाणा की गतिविधियों व उपलब्धियों बारे बैठक ले रहे थे। समीक्षा बैठक में विभाग के मंत्री गौरव गौतम ने पुष्प भेंट करते हुए मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। वन्दना दिसोदिया द्वारा एक प्रस्तुति के माध्यम से विभाग की गतिविधियां व उपलब्धियां भी प्रस्तुत की गई। प्रशिक्षण, आईटीआई का प्रतिष्ठानों के साथ ज्ञापन समझौता, आईटीआई संस्थानों में भवन रिपेयर के कार्य व सीएसआर के तहत प्रयोगशाला/आईटीआई का उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता

पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं भारत: एस. जयशंकर

तीखी बहस

पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को एक दलाल देश कहा। उनका इशारा इस संघर्ष में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की ओर था। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों में कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि 1981 से ही अमेरिका उस देश का इस्तेमाल करता आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संसद परिसर में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक में जयशंकर ने उपस्थित लोगों से कहा, हम कोई दलाल देश नहीं हैं। बैठक में सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत इस मुद्दे पर चुप नहीं है, बल्कि लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पश्चिम एशिया के हालात पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

भारत हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरी कदम उठा रहा: विदेश मंत्री जयशंकर

सरकार ने कहा कि भारत हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरी कदम उठा रहा है। कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार के जवाबों को असंतोषजनक बताते हुए लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा, विदेश नीति और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए।

सरकार ने दोहराया कि उसकी प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि देश को एकजुट रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत की प्रतिक्रिया कमजोर है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज किया।

सरकार ने यह भी बताया कि उसका सबसे बड़ा फोकस खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें अब तक सफलता मिली है।

पाकिस्तान की भूमिका पर सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने पाकिस्तान को लेकर साफ कहा कि वह लंबे समय से अमेरिका के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। विदेश मंत्री के हवाले से कहा गया कि भारत ऐसी भूमिका नहीं निभाता और अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी तीसरे देश के जरिए अपनी कूटनीति नहीं करता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत की प्रतिक्रिया कमजोर है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज किया। सरकार ने बताया कि ईरान में भारतीय प्रतिनिधियों ने तुरंत जाकर संवेदना जताई थी और हर स्तर पर भारत सक्रिय है।

टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी

गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद रहे। सरकार इस बैठक के जरिए सभी दलों को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रतिभागियों के सामने विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें पश्चिम एशिया के हालात, भारत के हित और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दी विपक्ष की ओर से कांग्रेस के तारिक अनवर और मुकुल वासनिक, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बीजद के सस्मित पात्रा शामिल हुए हैं। जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा बैठक में पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने बैठक से दूरी बनाई है और राहुल गांधी भी इसमें शामिल नहीं हुए।

किसानों को 2013 से पहले अधिग्रहित जमीन पर भी मिलेगा बढ़ा मुआवजा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण मामलों में उचित मुआवजे की सांविधानिक गारंटी को कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति और ब्याज वित्तीय बोझ की मात्रा पर निर्भर नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। एनएचएआई ने 4 फरवरी, 2025 के फैसले की समीक्षा मांगी थी। इस फैसले में कहा गया था कि 2019 का निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। 2019 के फैसले में एनएचएआई अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के किसानों को मुआवजा और ब्याज देने की बात थी। भूस्वामियों को देय ब्याज भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार नौ फीसदी होगा। यह एनएचएआई अधिनियम के पांच फीसदी की सीमा के अनुसार नहीं होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट।

केंद्र सरकार ने उड़ान 2.0 को दी मंजूरी

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के संशोधित संस्करण (उड़ान 2.0) को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू होगी, जिसका लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट को विकसित करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की

बैठक में 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना-संशोधित उड़ान के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए भारत सरकार के बजटीय सहयोग से कुल 28,840 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। संशोधित उड़ान योजना के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 12,159 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 3,661 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बाजार के लंबे समय तक विकास की आवश्यकता को देखते हुए एयरलाइन ऑपरेटरों को वीजीएफ सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसकी राशि 10,043 करोड़ रुपये होगी।

गुजरात विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित

गांधीनगर: गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। बिल पारित होने के बाद सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों ने समर्थन जताते हुए जय राम के नारे लगाए और मेज थपथपाकर स्वागत किया। वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने इस बिल को समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला बताया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। जिसके बाद सदन में 7 घंटे में लंबी चर्चा हुई।

हिमाचल विधानसभा: विपक्ष का वॉकआउट, सीएम का पलटवार

सदन में चर्चा

पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप, मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ की अनियमितता उजागर

टीम एक्शन इंडिया
पंकज शर्मा

शिमला। बजट अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि राज्य का बजट पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार किया गया है और इसमें किसी प्रकार का छिपाव नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल के साथ विस्तार से विचार-विमर्श के बाद वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले 3000-4000 करोड़ रुपये का कृत्रिम घाटा दिखाकर योजनाएं बनाई जाती थीं, जबकि इतनी राशि वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनी, तब प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार भी तुरंत नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व जयराम सरकार को आरडीजी और जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में बड़ी राशि प्राप्त हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश पर भारी कर्ज का बोझ छोड़ा गया।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पहले दिन कर्नाटक का जलवा, धनीश और अंजलि ने जीते स्वर्ण

□ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले दिन तैराकी स्पर्धाओं में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा कायम किया, जबकि ओडिशा और मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी पदक तालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, प्रतियोगिता के शुरूआती दिन पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल में कर्नाटक के धनीश एन और महिला वर्ग में ओडिशा की अंजलि मुंडा ने स्वर्ण पदक जीता

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले दिन तैराकी स्पर्धाओं में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा कायम किया, जबकि ओडिशा और मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी पदक तालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रतियोगिता के शुरूआती दिन पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल में कर्नाटक के धनीश एन और महिला वर्ग में ओडिशा की अंजलि मुंडा ने स्वर्ण पदक जीतकर टूनार्मेंट का शानदार आगाज किया। धनीश ने 2:03.55 सेकंड का समय निकालते हुए अपने ही राज्य के खिलाड़ी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा, जबकि अंजलि ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। पहले दिन तैराकी में कर्नाटक का दबदबा देखने को मिला, जहां टीम ने छह में से पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कर्नाटक के मणिकांत एल और मेघांजलि ने दो-दो स्वर्ण पदक जीतकर टीम की बढ़त को और मजबूत किया। मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी निराश नहीं किया और एक रजत व एक कांस्य पदक जीतकर अपने अभियान की शुरूआत की। इस पहले संस्करण में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो नौ खेलों में कुल 106 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

एथेलिक्स का आयोजन 30 मार्च से

टीम एक्शन इंडिया

जगदलपुर। भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और अदम्य खेल भावना को एक नया राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर में आयोजित की जा रही । बस्तर संभाग मुख्यालय, जगदलपुर में 'प्रथम खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स-2026' के तहत एथेलिक्स का आयोजन 30 मार्च से होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक खेल उत्सव के लिए देशभर के 26 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों का आगमन रायपुर में हो रहा है , जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। बस्तर के धरमपूरा के क्रीड़ा परिसर में आयोजित होने वाले प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड की टीमें भी पूरी तैयारी के साथ शिरकत कर रही हैं।

रायपुर : विवेकानंद विमानतल में केन्द्रीय खेल मंत्री मांडविया का हुआ भव्य स्वागत

रायपुर। केन्द्रीय खेल एवं श्रम कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया का प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अगुवाई में विवेकानंद विमानतल में बुधवार को भव्य स्वागत हुआ। केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया एक दिवसीय प्रवास में रायपुर पहुंचे। खेलो इंडिया अभियान के तहत आयोजित स्पर्धा का शुभारंभ के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान उनका लोककलाकारों व खिलाड़ियों द्वारा स्वागत किया गया। केन्द्रीय मंत्री मांडविया का विमानतल में मंत्री रामविचार नेताम, प्रदेश महामंत्री ड़ॉ. नवीन मारकंडे, विधायक गण सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, सुशांत शुक्ला, महापौर मीनल चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन, अपैक्स बैंक अध्यक्ष केदार गुप्ता, कार्यालय प्रभारी आशोक बजाज, सह कार्यालय प्रभारी प्रितेश गांधी, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नलिनेश ठोकने, अमित चिमनानी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, रायपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्याम नारंग, रायपुर ग्रामीण जिला प्रभारी सुरेन्द्र पाटनी, प्रदेश सत्कार संयोजक आकाश विग,झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक संजूनारायण सिंह सहित पार्टी पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण को मिलेगी नई दिशा

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर। संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन की अध्यक्षता में स्क्रिप्ट समिति के गठन हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रदेश में फिल्म निर्माण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने तथा छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत को सिनेमा के माध्यम से व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखी जा रही है। संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य ने सिनेमा और संस्कृति के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों और क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए।
बैठक में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. राजन यादव, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फोटो अधिकारी श्री अभिमन्यु सिन्हा, प्रसार भारती आकाशवाणी रायपुर से पद्मश्री डॉ. राधेश्याम तारक तथा प्रसार भारती दूरदर्शन रायपुर के कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.के. पाठक उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुंबई से फिल्म अभिनेता श्री भगवान तिवारी ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए फिल्म निर्माण के व्यावहारिक पहलुओं और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक में सदस्य सचिव के रूप में उप संचालक श्री उमेश मिश्रा ने समन्वय की भूमिका निभाई।
बैठक के दौरान स्क्रिप्ट समिति के गठन की रूपरेखा, कार्यप्रणाली और चयन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोककथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, जनजीवन और परंपराओं पर आधारित सशक्त और गुणवत्तापूर्ण पटकथाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थानीय विषयवस्तु पर आधारित फिल्मों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

बक्सर जेल में स्थित वामन भगवान मंदिर पूजा करने जा पाएंगे आम लोगः सम्राट चौधरी

व्यवस्था

□ बटुक वामन भगवान के मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जाएगी

टीम एक्शन इंडिया

पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बक्सर जेल परिसर में स्थित भगवान विष्णु के पांचवें अवतार बटुक वामन भगवान के मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना के बाद अब कोइलवर से बक्सर तक मैरिन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने बक्सर के किला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। बक्सर में हाल ही में सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है और यहां देश का सबसे बड़ा कोल्ड ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट भी स्थापित किया गया है। वर्ष 2005 से पहले बिहार में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उस समय पटना से बक्सर आने में चार से पांच घंटे लगते थे, जबकि आज यह दूरी दो घंटे में पूरी हो रही है। बक्सर-चौसा सड़क का निर्माण जारी है और गंगा नदी पर फोरलेन पुल बनाया जा रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सड़कों का विस्तार के बाद 1 लाख 40 हजार किलोमीटर सड़क है जबकि पहले यह आंकड़ा महज 6 हजार किलोमीटर था। बिहार का बजट 6 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये हो गया है। बिजली क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 17 लाख उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख हो गए हैं।

टीवीएस मोटर कंपनी ने लॉन्च किया टीवीएस किंग का वादा 3.0

ओनरशिप

□ उपभोक्ताओं को सहयोग प्रदान करने की टीवीएस मोटर कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है

टीम एक्शन इंडिया

मंडीः दुनिया की अग्रणी दोपहिया एवं तिपहिया निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस किंग का वादा 3.0 के लॉन्च की घोषणा की है। टीवीएस किंग थ्री-व्हीलर फैमिली के लिए कस्टमर-वैल्यू सपोर्ट की यह पहल इसके पिछले संस्करणें की सफलता को आगे बढ़ाते हुए उपभोक्ताओं को मिलने वाले फायदों का दायरा भी बढ़ाती है। वादा 3.0 के साथ टीवीएस मोटर कंपनी अपनी प्रतिबद्धता को सिर्फ वाहनों के स्वामित्व तक ही सीमित नहीं रखती बल्कि अपने उपभोक्ताओं एवं उनके परिवारों के लिए सुरक्षा और कल्याण को भी प्राथमिकता देती है।

टीवीएस किंग का वादा 3.0 एक व्यापक ओनरशिप पैकेज लेकर आया है, जिसे उपभोक्ता एवं उनके परिवारों को मन की शांति, बेहतर वित्तीय सुरक्षा और कम डाउनटाईम का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सटेंडेड वारंटी, फ्री मेंटेनेन्स सर्विसेज एवं रोडसाईड असिस्टेन्स के साथ यह योजना व्यक्ति एवं परिवार की सुरक्षा के फायदे देती है। इस तरह यह मोबिलिटी के दायरे से बढ़कर उपभोक्ताओं को सहयोग प्रदान करने की टीवीएस मोटर कंपनी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। टीवीएस किंग का वादा 3.0 के मुख्य फायदों में शामिल है।

योगी सरकार में वन स्टॉप सेंटर बने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सहारा

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊः उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का वन स्टॉप सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 55,134 प्रकरणों में महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जो इस व्यवस्था की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दिखाता है। यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जिन्हें संकट की घड़ी में तुरंत सहारा मिला है। इसके अंतर्गत 26,450 मामले पुलिस के माध्यम से आए, जबकि 7,551 महिलाएं खुद सहायता के लिए आगे आईं यानी सिस्टम तक पहुंच और उस पर भरोसा दोनों तेजी से बढ़ा है।

हर चैनल से जुड़ा सिस्टम, हर पीड़िता तक पहुंच

वन स्टॉप सेंटर

अब एकीकृत व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। महिला हेल्पलाइन से 8,506, बाल कल्याण समिति से 6,433 और अन्य माध्यमों से 5,560 मामले सामने आए। इसके अलावा विभिन्न विभागों के जरिए भी महिलाओं को सहायता मिली। यह दिखाता है कि अब व्यवस्था अलग-अलग हिस्सों में बंटी नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर पीड़ित महिला को हर जरूरी मदद उपलब्ध करा रही है।

हर तरह की समस्या का एक ही समाधान केंद्र

इन प्रकरणों में सबसे अधिक 34,565 मामले सिविल विवादों से जुड़े हैं, जबकि 14,268 मामले घरेलू हिंसा के हैं। इसके अलावा यौन हिंसा, जेंडर आधारित हिंसा और साइबर अपराध से जुड़े मामले भी हैं। साफ है कि वन स्टॉप सेंटर अब केवल एक सेवा नहीं, बल्कि महिलाओं से जुड़ी हर समस्या के समाधान का केंद्र बन चुके हैं।

चेतक स्क्रीन अवार्ड्स, 24 नॉमिनेशंस के साथ धुरंधर सबसे आगे

टीम एक्शन इंडिया

शिमलाः द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की 'स्क्रीन एकेडमी' ने आगामी 5 अप्रैल को होने वाले 'चेतक स्क्रीन अवार्ड्स' के लिए सभी 31 श्रेणियों में नामांकनों की घोषणा कर दी है। यह समारोह 2025 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के सम्मान में आयोजित किया जाएगा।आदित्य धर की स्पाय थ्रिलर 'धुरंधर' 24 नॉमिनेशंस के साथ सबसे आगे रही, जबकि मोहित सूरी की 'सैयारा' ने 17 और नीरज घेवान की 'होमबाउंड' ने 15 श्रेणियों में अपनी जगह बनाई। ये नॉमिनेशंस थिएटर और ओटीटी , दोनों प्लेटफॉर्म्स की फिल्मों के लिए हैं, जो आज के भारतीय सिनेमा की बदलती तस्वीर को दशार्ते हैं।1995 में शुरू हुए 'स्क्रीन अवार्ड्स' अपनी संपादकीय निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। इसका संचालन 'स्क्रीन एकेडमी' करती है, जो 50 से अधिक दिग्गज फिल्मकारों, कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों की एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संस्था है। इस साल, एकेडमी के 95 प्रतिशत से ज्यादा सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 'ओलंपिक पद्धति' का इस्तेमाल किया गया।

चौथे वार्षिक स्नो टेल्स कार्यक्रम का सफल आयोजन, इंसानों और कुत्तों का अनोखा संगम

पशु कल्याण

□ कुल्लू जिले के सेथन में चौथे वार्षिक स्नो टेल्स कार्यक्रम का सफल आयोजन किया

टीम एक्शन इंडिया

कुल्लूः हिमाचल प्रदेश में पशु कल्याण के समर्थन में देश का सबसे बड़ा स्नो शो मनाली स्ट्रेज ने स्नो मैराथन लीग के सहयोग को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सेथन में चौथे वार्षिक स्नो टेल्स कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस आयोजन में कुत्तों और उनके मानव साथियों ने भाग लेकर करुणा, समुदाय और पशु कल्याण का एक सुंदर संदेश दिया।इस वर्ष 24 कुत्तों और उनके मानव साथियों ने डॉग-ह्यूमन स्नो रेस में भाग लिया। हम्पटा वैली के किनारे बसे सेथन के बर्फ से ढके मनमोहक दृश्य इस आयोजन के दौरान जीवंत हो उठे, जहां उत्साहित कुत्तों की भौंक और प्रतिभागियों के जोश से पूरा माहौल गूंज उठा। इस अनोखी रेस में भाग लेने के लिए देशभर से प्रतिभागी पहुंचे, जिनमें कुछ लोग मुंबई से भी आए।स्नोटेल्स अब एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन बन चुका है और यह कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति जिलों में मनाली स्ट्रेज के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। स्नो टेल्स के संस्थापक और स्नो मैराथन लीग के संस्थापक गौरव शिमार ने कहा, ह्लपहाड़ी इलाकों में, जहां पशु चिकित्सा सेवाएं सीमित होती हैं, मनाली स्ट्रेज घायल और बीमार जानवरों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन शिक्षा, टीकाकरण और नसबंदी के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान भी तैयार करता है। स्नो टेल्स जैसे आयोजन न केवल कुत्तों और उनके प्रेमियों का उत्सव हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि पशु कल्याण स्वस्थ, सुरक्षित और संवेदनशील समाज से गहराई से जुड़ा है। मनाली स्ट्रेज की सह-संस्थापक डॉ. बेकी मेटकाफ ने कहा, स्नो टेल्स हमारे साल के सबसे खुशहाल दिनों में से एक है, क्योंकि यह उन लोगों को एक साथ लाता है जो सच में जानवरों की परवाह करते हैं।

बस्तर में हार्डकोर नक्सली कमांडर पापाराव सहित कुल 18 माओवादियों का आत्मसमर्पण

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बस्तर संभाग के जगदलपुर में मोस्ट वॉन्टेड हार्डकोर नक्सली कमांडर पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह घटनाक्रम बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस आत्मसमर्पण को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार बताते हुए कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और बस्तर की धरती पर हिंसा की विचारधारा पराजित होती स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक भय और हिंसा का वातावरण बनाने वाली माओवादी विचारधारा अब समाप्ति की ओर है और बस्तर तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और पुनर्वास केंद्रित नीतियों के कारण भटके हुए युवा अब मुख्यधारा में लौटने का विश्वास पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिले, तो हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के मार्ग को अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर में बंदूक की आवाज नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से हो रहे कार्यों ने बस्तर के जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि नक्सलमुक्त भारत का संकल्प अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने सुरक्षाबलों के साहस, समर्पण और रणनीतिक कार्रवाई की भी सराहना की। माओवाद के पूर्ण खात्मे के साथ बस्तर में शांति, विकास और विश्वास की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ देश के सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

एमएमएमयूटी में गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन व शिलान्यास किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

नौ सालों में यूपी में तीन गुना बढ़ी महिला श्रम शक्तिः सीएम योगी आदित्यनाथ

टीम एक्शन इंडिया

गोरखपुरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से बीते नौ सालों में महिला श्रम शक्ति तीन गुना बढ़ी है। वुमेन वर्क फोर्स का आंकड़ा 12 से बढ़कर 36 प्रतिशत को पार कर चुका है। वर्ष 2017 से पहले महिला सुरक्षा जहां एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब बिना भय के महिलाओं का तेजी से कामकाजी होना समाज में सुरक्षा का एक मानक बना है।सीएम योगी बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह गर्ल्स हॉस्टल, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सीएसआर फंड से बनवाया जाएगा। इसके निर्माण पर 13.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने एमएमएमयूटी में 4.67 करोड़ रुपये की लागत से बनी साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया और रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और वह स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होकर नए भारत के निर्माण में

अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उसी प्रकार की सुविधाएं देना आज की आवश्यकता है। इसे ही ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार हर बड़े महानगर में कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कर रही है। किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक यही है कि महिलाएं बिना भय घर से बाहर निकल सकें। 2017 के बाद सरकार की तरफ से इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम सबके सामने हैं। पहले पढ़ने के लिए यूपी से बाहर भेज देते थे बेटियों को

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में महिला सुरक्षा चुनौती थी। मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परिवार ऐसे थे, जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। आज यूपी के हर जनपद में बेटी बिना डर के पढ़ने जाती है, अन्य शहरों में कार्य करने जाती है। नौ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की संख्या 12 फीसदी से कम थी, वह आज बढ़कर 36 फीसदी से ज्यादा हो गई है। बेटा-बेटी में भेदभाव बंद होने पर कई गुना बढ़ेगी विकास की रफ्तार

सीएम योगी ने कहा कि सदन में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद से पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 2029 के चुनाव में यह लागू हो जाए। जब समाज में महिला-पुरुष का भेद समाप्त होता है तो सुखद अनुभूति होती है। अभिभावक जब बेटी-बेटे में भेद करना बंद करेंगे तभी विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी और तभी स्टेबिलिटी (स्थायित्व) आएगी। वर्तमान दौर में फोरेंसिक साइंस लैब की आवश्यकता को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले यूपी पुलिस के पास ग्रेड-1 की सिर्फ 02 फोरेंसिक साइंस लैब थीं। आज यूपी में ग्रेड-1 की 12 फोरेंसिक साइंस लैब हैं।

मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा दिए गए बेड लोन्स में से 10 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की : अनुराग ठाकुर

अर्थव्यवस्था

» मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान इसे मोदी सरकार द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बताया।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक 2016 में लागू की गई दिवाला और दिवालियापन संहिता को और मजबूत करेगा, जो कॉर्पोरेट संकट के समाधान के लिए एक एकीकृत और समयबद्ध ढांचा प्रदान करती है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसमें प्रभावी आर्थिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश की 140 करोड़ जनता ने विकास को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। 2016 में लागू आईबीसी को उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने वाला मजबूत इंजन बताया।

उन्होंने कहा कि जीएसटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक ढांचे में बड़े निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिसमें आईबीसी ने क्रेडिट अनुशासन, मूल्य अधिकतमकरण और निवेशक विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार द्वारा बैंकिंग सिस्टम की सफाई, एनपीए में कमी और क्रेडिट अनुशासन लागू करने के प्रयासों को रेखांकित किया तथा कांग्रेस शासन के दौरान हुए लापरवाह ऋण वितरण, क्रोनीवाद और आर्थिक कुप्रबंधन की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि आईबीसी और इसके संशोधन पुराने खराब कर्जों के समाधान के साथ वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ बना रहे हैं, जबकि राहुल गांधी रचनात्मक सुझाव देने, संस्थाओं का सम्मान करने और राष्ट्रीय हित में सुधारों का समर्थन करने की जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर रहे।

पीएनबी आरसेटी में नरम खिलौना निर्माण प्रशिक्षण का समापन

राजन पुरी

ऊना। पीएनबी आरसेटी ऊना द्वारा आयोजित 14 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नरम खिलौने बनाने और उन्हें बाजार में बेचने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया।

यह कार्यक्रम पीएनबी आरसेटी ऊना कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण केवल सीखने तक सीमित न रहे, बल्कि इसे रोजगार में बदलना ही इसका वास्तविक उद्देश्य है।

उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपना स्वयं का कार्य शुरू करें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।

अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूर्व सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री : जयराम ठाकुर

तथ्यहीन

» अपने बजट में बताने को जब कोई उपलब्धि नहीं है तो इसी तरह की तथ्यहीन बातें करनी पड़ रही हैं

चमन शर्मा

शिमला। बजट अनुमानों पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन है झूठ बोलने, झूठे आरोप लगाने और सदन को गुमराह बंद करने की नारे बाजी की।

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में चार बजट में मुख्यमंत्री के पास बताने के लिए कुछ नहीं है इसलिए पूर्व सरकार की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार को यह बात चुभती है कि प्रदेश के लोग हिम केयर की तारीफ करते हैं हमारी योजना की तारीफ करते हैं। मुख्यमंत्री जिस राह पर चल रहे हैं वह एक प्रदेश की मुखिया की राह नहीं है। वह लगातार विजिलेंस पर भाजपा के नेताओं पर फर्जी आरोप लगाने के बहाने खोजने के लिए दबाव बना रहे हैं। आरटीआई के दायरे से बाहर लाना उनकी इसी साजिश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री सिर्फ आप और प्रत्यारोप की राजनीति में ही माहिर हैं और वही लगातार कर रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अपने बजट में बताने को जब कोई उपलब्धि नहीं है तो इसी तरह की तथ्यहीन बातें करनी पड़ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं की इलाज सरकारी अस्पताल में होगा दूसरी तरफ कहते हैं कि एक ही मेडिकल कॉलेज में 100 करोड़ का घोटाला हो गया।

अगर घोटाला हो गया तो मुख्यमंत्री जांच करें जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री के आरोप में कोई तथ्य नहीं है और बताने के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए इस तरीके की औचित्यहीन बातें करके मुख्यमंत्री सदन का वक्त जाया कर रहे हैं।

नगर निकाय चावन को लेकर आरक्षण रोस्टर जारी

हामिद खान

चंबा। हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को लेकर जिला चंबा में आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में चंबा, चुवाड़ी और डलहौजी की तीनों अर्बन म्युनिसिपल बॉडीज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह रोस्टर तय किया।

जनसंख्या के आधार पर तैयार किए गए इस रोस्टर में चंबा नगर परिषद के 11 वार्डों में से दो वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) और एक वार्ड अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है। प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्डों का चयन किया गया। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से जुलाहकड़ी वार्ड को महिला एससी के लिए और हटनाला वार्ड को ओपन एससी के लिए आरक्षित किया गया। वहीं कसाकड़ा वार्ड को एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 11 में से 6 वार्ड महिलाओं और 5 वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सुल्तानपुर, चौगान, जनसाली और हरदासपुर व सुराड़ा वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित किए गए हैं।

डलहौजी नगर परिषद में परिसीमन (डिलिमिटेशन) के बाद जनसंख्या में बदलाव के चलते इस बार आरक्षण में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। यहां एक वार्ड एससी और एक वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किया गया है।

पूर्व सैनिकों के आश्रितों को मिली आर्थिक सहायता

राजन पुरी

ऊना। लांस नायक करम सिंह पीवीसी सैनिक कैंटीन, दौलतपुर चौक (ब्रह्मपुर) में बुधवार को पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों के आश्रितों को करीब 60 रुपये की आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए 7 कैंटीन मैनेजर सूबेदार शशि पाल की अध्यक्षता में सपन्न हुए इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रति परिवार 10-10 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान कैंटीन मैनेजर शशि पाल ने पूर्व सैनिकों को मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की।

ऊना में युवक को जान से मारने की धमकी, दो के खिलाफ मामला दर्ज

राजन पुरी

ऊना। थाना सदर के तहत संतोषगढ़ के एक युवक को जान से मारने की धमकी देने और उसका पीछा करने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में शुभम रायजादा निवासी संतोषगढ़ ने बताया कि गत दिवस वह अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए एक दुकान पर गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी प्रियंकल निवासी गांव बहड़ाला और आशुतोष निवासी गांव मलाहत वहां पहुंचे और उसे ढूंढने लगे।

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से तलाश किया। जब वह उनके हाथ नहीं लगा तो उन्होंने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं।

इतना ही नहीं, जब वह वहां से निकल गया तो आरोपियों ने दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में उसका पीछा करते हुए गांव जनकौर तक उसका पीछा किया।

घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाना सदर ऊना में शिकायत दर्ज करवाई। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार दानों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संक्षिप्त खबरें

शिक्षा, कृषि व पशुपालन ऋण को भी प्राथमिकता दें बैंक : डीसी कांगड़ा

विजय समयाल

धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बैंकों से शिक्षा, कृषि एवं अन्य उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ढगवार दुग्ध प्लांट भी शुरू होने जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऐसे में बैंकों को गौ-पालन जैसे क्षेत्रों में भी किसानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।

यह विचार उन्होंने आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति, जिला समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक की उपलब्धियों एवं प्रगति की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी बैंकों को ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए तथा शिक्षा और कृषि ऋण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

बैठक का संचालन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक कांगड़ा पृथ्वी रणवीर ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 8945.20 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 2025 तक बैंकों ने 6677.01 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 74.64 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है।

उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक जिले में बैंकों द्वारा कुल 48986.37 करोड़ रुपये जमा किए गए तथा 12779.68 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, जिससे ऋण-जमा अनुपात 26.09 प्रतिशत रहा। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए बैंकों को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता बताई गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तिमाही तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 53.61 प्रतिशत तथा गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 308.32 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति दर्ज की गई।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने खूबसूरत कसौली पहल के लिए स्थानीय पंचायतों के साथ साझेदारी की

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गैर सरकारी संगठन वेस्ट वॉरियर्स और स्थानीय पंचायतों के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक समुदाय.आधारित कचरा प्रबंधन पहल शुरू की है।यह परियोजना गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की प्रभाव आधारित कार्य संस्कृति को दर्शाती है। खूबसूरत कसौली पहल के तहत 66.5 मीट्रिक टन से अधिक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोका गया है साथ ही स्थानीय निवासियों को जिम्मेदार कचरा प्रबंधन अपनाने और इसमें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है।2023 में शुरू हुई यह पहल चार पंचायतों कसौली गरखल, गरखल सनावर, गुलहाड़ी और धर्मपुर में लागू की गई है।

इसका उद्देश्य खुले में कचरा फेंकने और जलाने की समस्या,सूखे कचरे के व्यवस्थित संग्रह की कमी और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। 700 से अधिक घरों को यूनिक आईडी और सूखे कचरे के संग्रह बैग प्रदान किए गए जिनमें से 320 से अधिक परिवार नियमित रूप से कचरे के पृथक्करण और संग्रह में भाग ले रहे हैं। कचरा प्रबंधन को और सशक्त बनाने के लिए एक वेस्ट बैंक स्थापित किया गया।

विधान सभा अध्यक्ष ने दी मुख्यमंत्री को 63वें जन्मदिन की बधाई

चमन शर्मा

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने 27 मार्च 1964 को जन्मे हि0प्र0 के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके 63वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

अपने बधाई सन्देश में पठानियां ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू एक नेक दिल इन्सान, परिश्रमी राजनेता तथा कुशल प्रशासक हैं। पठानियां ने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इस प्रदेश को उत्तम तथा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं।

उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री हि0प्र0 को एक स्वावलम्बी, उत्तम तथा आत्म निर्भर राज्य की दिशा में आगे ले जाने में तत्पर है। पठानियां ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समृद्व तथा सुखद जीवन की कामना करते हुए उनकी दीर्घायू की कामना की है।

बेहड़ जसवां में अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज

राजन पुरी

ऊना। उपमंडल अंब के तहत बेहड़ जसवां में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोतल देसी शराब बरामद की हैं। जानकारी के मुताबिक गत रात्रि थाना अंब की टीम एएसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस जब बेहड़ जसवां क्षेत्र में पहुंची तो वहां एक व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोतल देसी शराब बरामद की गई।

आरोपी की पहचान नवीन कुमार निवासी गांव धंधड़ी के रूप में हुई है। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर ही शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफआबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया।

ठठूंह-तमलेट-बंगाणा लिंक रोड बदहाल, गड्ढों और बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा

राजन पुरी

ऊना। उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत ठठूंह से वाया तमलेट होते हुए बंगाणा तक जाने वाली महत्वपूर्ण लिंक रोड इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यह मार्ग अब सुविधा के बजाय लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनता जा रहा है। जगह-जगह गहरे गड्ढे पड़ने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आए दिन छोटे-बड़े हादसों की आशंका भी लगातार बनी हुई है।

यह सड़क न केवल स्थानीय गांवों को जोड़ने का मुख्य माध्यम है, बल्कि स्कूली ब%चों, कर्मचारियों, व्यापारियों और मरीजों के आवागमन के लिए भी बेहद अहम है। बावजूद इसके, लंबे समय से इस मार्ग की सुध नहीं ली गई है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहन चालक कई बार संतुलन खो बैठते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों में वतन सिंह, रवि कुमार, सुनील संधू, अंकुश कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार, करण ठाकुर, ओम प्रकाश, राजकुमार और ओंकार दास शास्त्री कहना है कि इस मार्ग पर लगातार चल रहे ओवरलोड टिप्पर और ट्रैक्टर सड़क की दुर्दशा के मुख्य कारण हैं।

भारी वाहनों के दबाव से सड़क की परत उखड़ चुकी है और कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके साथ ही इन वाहनों से गिरने वाली बजरी और रेत सड़क पर फैल जाती है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है और खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग बेहद खतरनाक बन जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा इस समस्या की अनदेखी की जा रही है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क की तत्काल मरम्मत करवाई जाए और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

जमानत के बाद तिहाड़ जेल से निकलकर ऊना पहुंचे अनिल डडवाल

राजन पुरी

ऊना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एप्सटीन फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिगी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जिला ऊना के कांग्रेस नेता अनिल डडवाल को जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

रिहाई के बाद अनिल डडवाल अपने गृह जिला ऊना पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देसराज गौतम के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनिल डडवाल ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने केवल सरकार की दमनकारी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिगी पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। डडवाल ने कहा कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वह इस मामले में कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे।

जिला रोजगार कार्यालय ऊना में साक्षात्कार 28 मार्च को

टीम एक्शन इंडिया

ऊना। जिला रोजगार कार्यालय ऊना में 28 मार्च को प्रातः 10.30 बजे साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। यह साक्षात्कार इम्यूनटेक लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड गोंदपुर और एचपीजीआइसीएस कंट्री लिक्यूड बॉटलिंग प्लांट मैहतपुर द्वारा लिया जाएगा, जिसमें ट्रेनी टेक्निशियन के दो पद और दो पद अप्रेंटिसशिप के तौर पर भरे जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार में हिस्सा लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता ईलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई तथा डिप्लोमा, स्नातक होना अनिवार्य है।

एजी कार्यालय की ऑनलाइन व्यवस्था से सेवानिवृत्त कर्मचारी बेहाल, बढ़ी दुविधा

हामिद खान

चंबा। लेखाकार जनरल कार्यालय द्वारा पेंशन प्रकरणों के लिए अनिवार्य की गई ऑनलाइन प्रक्रिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए गले की फांस बन गई है। तकनीकी खामियों और अधूरी व्यवस्था के कारण प्रदेश भर के कर्मचारी गंभीर दुविधा और मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। न्यू पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के अध्यक्ष सुनील जरियाल ने इस संबंध में प्रेस नोट जारी कर विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ ,त कार्यालय ऑफलाइन पेंशन केस स्वीकार नहीं कर रहा और उन्हें लगातार वापस भेज रहा है, वहीं दूसरी ओर मानव संपदा पोर्टल पर आवश्यक विकल्प ही उपलब्ध नहीं हैं। जरियाल ने बताया कि स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब पोर्टल पर केवल 2 से 6 माह पुराने केस ही दिख रहे हैं। वर्ष 2024, 2025 और उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का डेटा सिस्टम में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसके चलते सैकड़ों कर्मचारी अपने पेंशन अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

सुनील जरियाल के अनुसार, सबसे अधिक समस्या उन कर्मचारियों को आ रही है जो पहले नई पेंशन स्कीम में थे और अब पुरानी के दायरे में आए हैं। 1 जनवरी 2026 से जारी नए निर्देशों के बाद विभागीय क्लर्क और स्टाफ भी असमंजस में हैं। ट्रेजरी और एजी कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सुनील जार्याल का कहना है कि पेंशन केस ऑनलाइन भेजने का विकल्प साइट पर नहीं आ रहा है और ऑफलाइन फाइलें एजी ऑफिस स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में कर्मचारी आखिर कहां जाएं?

महासंघ ने मुख्यमंत्री और वित्त सचिव से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं पोर्टल की खामियों को तत्काल एनआईसी के माध्यम से दूर किया जाए। जब तक ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह ठीक नहीं होता, तब तक ऑफलाइन पेंशन मामलों को स्वीकार कर उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

आपदा जागरूकता दिवस पर निकाला जाएगा नागरिक एकजुटता मार्च

राजन पुरी

ऊना। कांगड़ा में वर्ष 1905 में आएं भूकम्प की वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए 4 अप्रैल को आपदा जागरूकता दिवस के अवसर पर नागरिक एकजुटता मार्च निकाला जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि यह मार्च न्यू बस स्टैंड ऊना से डीसी ऑफिस चैक तक निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों में इवैक्यूएशन ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अप्रैल माह के दौरान पंचायत स्तर पर ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से लोगों को भूकंप रोधी निर्माण प्रथाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपदा जागरूकता दिवस रा%यव्यापी अभियान के रूप में मनाया जाता है जिसके तहत रा%य, जिला और समुदाय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें भूकंप आपदा पूर्वाभ्यास, विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण शामिल हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य समुदाय को आपदा प्रबंधन की तैयारियों के प्रति जागरूक करना और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना है।

पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए टैक्स को तुरंत वापस ले सरकार : भाजपा

चमन शर्मा

शिमला। शिमला जिला भाजपा प्रवक्ता जितेन्द्र भोटका, पूर्व उपाध्यक्षा सक्षम गुड़िया बोर्ड रूपा शर्मा, शशांक अत्री, प्रीतम ठाकुर ने बुधवार को जारी संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त टैक्स और सेस का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनविरोधी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज बनकर इस निर्णय का विरोध करती रहेगी और सरकार को तुरंत इसे वापस लेना चाहिए। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर करीब 5 रुपये तक अतिरिक्त सेस लगाकर आम आदमी पर सीधा आर्थिक बोझ डाल दिया है। उनका कहना है कि इस फैसले से प्रदेश में महंगाई और बढ़ेगी, जिसका सबसे अधिक असर किसान, बागवान, ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी तथा आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इन्होने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर पड़ता है।

पेट्रोल-डीजल महंगा होने से फल, सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होना तय है, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ेगी। इन्होने कहा कि कि ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपने आर्थिक कुप्रबंधन को छिपाने के लिए जनता पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। शिमला भाजपा पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया अतिरिक्त सेस तुरंत वापस लिया जाए और महंगाई से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

मनाली बौद्ध मठ में धर्म गुरु दलाईलामा की जीवनी पर छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ

टीम एक्शन इंडिया
नरेंद्र अंगारिया

केलांग । केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा जुलाई 2025 से जून 2026 तक' घोटोन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । जिसके तहत बौद्ध गुरु 14वें दलाई लामा की 90वीं वर्षगांठ विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत क्षेत्रीय कुल्लू घोटोन समिति द्वारा 25 मार्च 2026 को बौद्ध मठ मनाली में एक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । बौद्ध धर्म गुरु दलाईलामा की जयंती को 'करुणा वर्ष' के रूप में मनाते हुए इस छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उनकी 'जीवनयात्रा और विरासत को समर्पित प्रदर्शित किया गया । छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक एवं मनाली बौद्ध मठ कार्यसमिति के संरक्षक रवि ठाकुर ने किया । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा विनम्र उद्देश्य परम पावन दलाईलामा के असाधारण जीवन और उनकी शिक्षाओं एवं स्थायी विरासत को जन-जन तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी में दुर्लभ और महत्वपूर्ण छायाचित्रों का एक विशेष संकलन प्रस्तुत किया जाएगा, जो परम पावन के अद्भुत जीवन-यात्रा को दर्शाता है। तिब्बत में उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर निर्वासन के लंबे और सार्थक काल तक, तथा शांति, करुणा और अहिंसा के लिए उनके निरंतर प्रयासों और तिब्बती संस्कृति, धर्म और पहचान को संरक्षित करने के उनके सतत प्रयासों का पूरा विवरण इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने कहा कि करुणा की प्रतिमूर्ति दलाईलामा का प्रत्येक चित्र एक ऐसी कहानी कहता है जो सीमाओं से परे जाकर विश्वभर के लोगों के हृदय को प्रेरित करता है। रवि ठाकुर ने कहा कि जिस तरह आज के समय में विश्व चारों ओर से तनाव की स्थिति से गुजर रहा है खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है

नन्हे कदम बड़ी उड़ान के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल झबोला में प्रथम ग्रेजुएशन सेरेमनी का शानदार आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। बुधवार को डीएवी पब्लिक स्कूल झबोला ने प्रथम ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नर्सरी से लेकर यूकेजी कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत अभिभावकों को तिलक लगाकर हुआ । इसके पश्चात पवित्र हवन का आयोजन किया गया जिसमें अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने अहम भूमिका निफाई। इसके बाद कार्यक्रम का मुख्य एवं आकर्षक केंद्र ग्रेजुएशन सेरेमनीआयोजित की गई जिसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों द्वारा प्रशंसा स्वरूप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य रवि कुमार कारवा ने बच्चों को नशे जैसी हानिकारक एवं बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा दी और बताया कि विद्यालय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की समृद्ध शिक्षा भी दी जाती है।कार्यक्रम के अंत में बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी।

प्रदेश सरकार का बजट पेंशनर्ज विरोधी, दिशाहीन और विकासहीन: सीआर वर्मा

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक चेत राम वर्मा ने सरकार द्वारा 2026.27 के बजट को पेंशनर्ज विरोधी, दिशाहीन और विकासहीन करार दिया है तथा इस बजट में पेंशनरों की लंबित आर्थिक देनदारियों के बारे में समयबद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसकी वजह से प्रदेश के पेंशनरों में बहुत नाराजगी है, इतिहास में पहली बार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में देखने को मिला है कि पेंशनरों और कर्मचारियों को 13 प्रतिशत महगाई भत्ते सहित अन्य देन दारियों की अदायगी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इससे तो यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन की बजह से नियत ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार लंबित आर्थिक लाभ देने की बजाये सब कुछ फ्रीज

करने के चकर में है क्योंकि सरकार ने पहले अपने मन्त्रीयों, विधायकों, अध्यक्षों, उपाध्यक्ष, सलाहकारों व अन्य चेहतों को खुश करने के लिए दोगुना वेतन भते बढ़ा दिए थे और अब मामूली कटौती करके वित्तीय संकट की भरपाई करने परिचय दे रहे है जो सही नहीं है और जनता सब कुछ समझती है। चेत राम वर्मा ने सभी संगठनों के पेंशनरों से आग्रह किया है कि 30 मार्च 2026 को प्रस्तावित पेंशनरों के हकों के लिए चैड़ा मैदान शिमला में धरना प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमे जिला के सभी संगठनों के पदाधिकारियों सहित पेंशनर्स भारी संख्या में भाग लेंगे क्योंकि सरकार द्वारा पेंशनरों के हितों की अनदेखी की है तथा सरकार के इस रवैया से हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है और न ही भविष्य में भी कुछ भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। इसलिए सरकार को जगाने और मांगों को याद करवाने के लिए धरना प्रदर्शन जरुरी है ताकि सरकार को पेंशनरों की देन दारियों के भुगतान के बारे में जगाया जा सके इसीलिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जला संयोजक चेत राम वर्मा ने जिला के सभी पेंशनरों से आग्रह किया है कि कुछ सरकारी समर्थक स्वयंभू, तथाकथित, गुमराह करने वाले जिन्होंने अपने आप को सरकारी प्रवक्ता, भोंपू और सरकार का धन्यवाद करने वाले चमचागिरी कर रहे है

31 मार्च को सायं पांच बजे तक बैंकों में प्रस्तुत करने होंगे कोषागार से पारित बिल- उपायुक्त

खेमचंद शास्त्री

मंडी। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला में कोषागार द्वारा पारित निधि निकासी के बिल 31 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे से पहले संबंधित बैंकों में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में कोषागारों में भारी भीड़ से बचने के लिए, निधि निकासी के सभी बिल 23 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे तक कोषागार में प्रस्तुत करने की तिथि वित्त विभाग की ओर से निर्धारित की गई थी। साथ ही संबंधित बैंकों को अधिकृत निकासी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के दृष्टिगत यह व्यवस्था की गई है।

सरकार वेतन कटौती के फैसले पर पुनर्विचार करे प्रवक्ता संघ: नरेश ठाकुर

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ बिलासपुर के अध्यक्ष नरेश ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष बलवंत ठाकुर महासचिव सुशील चन्देल, वित्त सचिव विकास चैहान, सुरेंद्र ठाकुर, सुरेंद्र मेहता, विनोद कौशल, मदन ठाकुर, संजीव कौशल, सुरेश कुमार, संदीप, श्रीकांत, राजीव चैधरी, जगदीप ठाकुर, पवन ठाकुर, राज कुमार, प्रशांत, सुरेंद्र धीमान, संजीव, राजेंद्र, यशपाल, गुरमीत, कमलजीत, बाबू राम, मनोज, कमल कांत, गौरव टाडू, विनोद, प्रेम सिंह, राजपाल, अरविंद, भूपेंद्र साख्यान, गुरभाग सिंह, रिंकू

सिंह, कमलजीत, पवन ठाकुर, अनुराधा, मेघा चैहान, सपना कलसी, तथा अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि ने कहा कि ग्रुप.बी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा स्थगित करने के निर्णय पर सरकार को तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रुप.बी श्रेणी प्रदेश के उस मध्यवर्गीय कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह वर्ग न तो उच्च आय वर्ग में आता है और न ही इसे किसी विशेष वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलता है। अधिकांश कर्मचारी हाउस लोन, वाहन लोन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के आर्थिक दबाव में पहले से ही जूझ रहे हैं। ऐसे में वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा स्थगित करने का निर्णय उनके मासिक बजट को सीधे प्रभावित करेगा और जीवनयापन पर प्रतिकूल असर डालेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है।

अनुपूरक मतदाता सूचियों के निर्माण हेतु कार्यक्रम जारी

टीम एक्शन इंडिया

कुल्लू। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए अनुपूरक मतदाता सूचियों को तैयार करने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार लाहौल क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों (पुनर्गठन/विभाजन से संबंधित पंचायतों को छोड़कर) में सामान्य निर्वाचन-2026 के लिए 01 अप्रैल 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए अनुपूरक मतदाता सूचियों का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है— -पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 28 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। -दावे एवं आपत्तियों पर पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्णय 02 अप्रैल 2026 तक लिया जाएगा। -अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। -अपीलों पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। -अनुपूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 को अथवा उससे पूर्व किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)ने आमजन को सूचित करते हुए कहा

जोगिंद्रनगर मेले में इस बार वॉलीबॉल ट्रॉफी का आयोजन बड़े स्तर पर, 16 टीमें लेंगी भाग, विजेता टीम को मिलेंगे 51 हज़ार

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। राज्य स्तरीय लघु शिवरात्रि मेला जोगिंदर नगर के अंतर्गत इस वर्ष वॉलीबॉल प्रतियोगिता को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। मेला समिति अध्यक्ष एवं एसडीएम जोगिंदर नगर मनीश चौधरी ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यह प्रतियोगिता पुलिस विभाग के विशेष सहयोग से करवाई जा रही है उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के सभी 12 जिलों से एक-एक टीम को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक स्थानीय टीम तथा तीन टीमें छात्रावासों से भाग लेंगी। इस प्रकार कुल 16 उत्कृष्ट टीमें प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए विजेता टीमों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 51,000 रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 31,000

रुपये तथा तृतीय स्थान के लिए 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मनीश चौधरी ने कहा कि इस बार वॉलीबॉल प्रतियोगिता को 'एंटी चिट्टा' थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने आगे बताया कि इच्छुक टीमें ऑनलाइन माध्यम से 1000 रुपये की पंजीकरण शुल्क जमा कर अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकती हैं। इसके लिए बैंक खाता संख्या 50100071762870 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक टीमें मोबाइल नंबर 8627972669 तथा 8580405276 पर संपर्क कर सकती हैं।

कोरोना काल में चिकित्सकों को लेकर उड़ाई खिल्ली का संगठन ने दिया जबाव

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रैस सचिव डा. विजय राय ने प्रैस को जारी बयान में कहा है कि कोविड.19 के दौरान हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के अप्रतिम योगदान और बलिदान का स्मरण हाल ही में सामने आए एक वीडियो में कोविड.19 महामारी के दौरान डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर कुछ अनुचित टिप्पणियां की गई हैं, वह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक और हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में उस भयावह दौर में लोगों के डर, असमंजस और पीड़ा को गहराई से समझते हैं। हालांकि, स्थिति के सही आंकलन के लिए उस समय की पूर्ण वास्तविकताओं और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के संघर्ष को याद करना भी अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन, लापरवाही नहीं, महामारी के शुरुआती दौर में जब वायरस नया था और वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, तब दूरी बनाए रखना, या कम से कम संपर्क में आना, कोई व्यक्तिगत विकल्प या लापरवाही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिस व्यवहार पर तंज कसे जा रहे हैं, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकारी दिशा.निर्देशों के तहत एक अनिवार्य और सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल था। इसका एकमात्र उद्देश्य संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना और मरीजों के साथ.साथ सीमित संख्या में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को बचाना था। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मोर्चे पर डटकर काम किया। भारी और घुटन भरी पीपीई किट पहनकर लगातार कई.कई घंटों तक मरीजों की देखभाल करना शारीरिक और मानसिक रूप से एक बेहद कठिन चुनौती थी, जिसे चिकित्सकीय वर्ग के कोरोना योद्धाओं ने पूरी निष्ठा से निभाया। दूसरों की जान बचाते हुए हमारे चिकित्सा जगत ने एक बहुत भारी कीमत चुकाई है। डा. राय ने कहा कि डाक्टर और मेडीकल स्टाफ के कई सहयोगी खुद इस खतरनाक वायरस का शिकार हुए हैं। सबसे पीड़ादायक यह है कि कर्तव्य का पालन करते हुए हिमाचल के कई डॉक्टरों ने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को कोविड के कारण हमेशा के लिए खो दिया। अपने घरों में अपनों को खोने के गहरे दुख के बावजूद, हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अपने आंसू पोंछकर अगले ही दिन वापस अस्पतालों में मरीजों की सेवा के लिए लौट आए। उन्होंने कहा कि उस अभूतपूर्व वैश्विक संकट के समय में, हिमाचल प्रदेश का चिकित्सा समुदाय जनता की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का यह अदम्य साहस, निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च पारिवारिक बलिदान आलोचना का नहीं, बल्कि हमारे समाज के गहरे

पंडोह में अग्निवीर भर्ती रैली में मंडी जिला के 399 युवा अभ्यर्थी हुए शामिल

खेमचंद शास्त्री

मंडी। सेना भर्ती कार्यालय मंडी की वर्ष 2025-26 की अग्निवीर भर्ती रैली तृतीय इंडिया रिजर्व बटालियन पंडोह के ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इस रैली में कुल्लू, मंडी एवं लाहौल-स्पिति जिलों के सीईई उत्तीर्ण 2,959 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। भर्ती निदेशक, एआरओ, मंडी कर्नल गौतम निशान्त ने बताया कि आज 25 मार्च, 2026 को मंडी जिला के 399 युवाओं ने भर्ती रैली में भाग लिया। प्रात: काल 1.6 किमी दौड़ के साथ आज भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई। दौड़ के दौरान सभी युवा अभ्यर्थियों में बहुत ही जोश और उत्साह देखने को मिला।

कांस्य पदक जीतकर हिमाचल कबड्डी ने रचा इतिहास: टेक चंद शर्मा

टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री

मंडी। मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित पांचवी कबड्डी फेडरेशन कप में हिमाचल को कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता है । यह जानकारी जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष टेक चंद शर्मा ने दी । उन्होंने बताया कि भारत के मध्य प्रदेश में कबड्डी फेडरेशन कप आयोजित किया गया जिसमें देश की आठ टॉप टीमों ने भाग लिया । यह कप महिला, पुरुष वर्ग खेला गया। हिमाचल ने पहली मर्तबा महिला व पुरुष कबड्डी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबला सर्विस के साथ हुआ । दुर्भाग्य से इस सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल टीम के कप्तान शिवांश ठाकुर जो जिला मंडी से ताल्लुक रखते हैं घायल हो गए जिस वजह से यह

मुकाबला हिमाचल के हाथ से निकल गया । उन्होंने बताया कि लड़कियों की टीम ने भी

दमखम दिखाया तथा उन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया। हिमाचल कबड्डी टीम में मंडी से शिवांश ठाकुर, रजत चौधरी और लड़कियों में भावना ठाकुर ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की है की हिमाचल कबड्डी टीम के कप्तान शिवांश ठाकुर और अन्य खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेल को और बेहतर बनाने के लिए हिमाचल कबड्डी संघ काम कर रहा है तथा ग्रामीण परिवेश से और बेहतर खिलाड़ी निकले जाएंगे जो देश और प्रदेश के लिए मेडल लेकर आएंगे। प्रदेश के लिए कांस्य पदक लेकर आए कबड्डी टीम के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जाएगा।

सरकारी कार्यालयों में 31 मार्च तक लागू होगा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, बकाया बिल चुकाने के निर्देश : अधिशासी अभियंता

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। विधुत मंडल जोगिंद्रनगर के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और भवन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। वरिष्ठ अधीक्षण अभियंता पूरण चंद द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों के बिजली कनेक्शनों में पर्याप्त अग्रिम शेष (बैलेंस) बनाए रखें, ताकि विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। इसके साथ ही वर्तमान पोस्टपेड कनेक्शनों के लंबित बिजली बिलों का तत्काल निपटान करना भी अनिवार्य बताया गया है। सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद संबंधित

कनेक्शन स्वतः ही प्रीपेड मोड में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। विभागाध्यक्षों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में सभी बिजली कनेक्शन समय-समय पर रिचार्ज किए जाते रहें और निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रीपेड खातों में पर्याप्त बैलेंस बना रहे, जिससे बिजली की सतत आपूर्ति प्रभावित न हो। यह सूचना व्यापक जनहित में जारी की गई है तथा संबंधित अधिकारियों को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव, सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज, विभागों को सौंपे दायित्व

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेला घुमारवीं के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में उप मंडल अधिकारी घुमारवीं गौरव चैधरी ने आज मेला ग्राउंड का विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड, जल शक्ति विभाग, नगर परिषद सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व शहर के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उप मंडल अधिकारी ने मेला स्थल के विभिन्न हिस्सों का दौरा

कर चल रही तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला यह राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ करना होगा। गौरव चैधरी ने बताया कि मेले के सफल संचालन के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली तथा यातायात प्रबंधन को लेकर विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के आरंभ से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्था, धरातल पर सुनिश्चित कर ली जाएंए ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनातीए साफ.सफाई की बेहतर व्यवस्था तथा निर्बाध पेयजल और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेले को और अधिक व्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से बड़े और छोटे झूलों तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए पुल के समीप अलग स्थान चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही मेला ग्राउंड से उक्त स्थान तक आने.जाने के लिए एक सुगम और सुरक्षित मार्ग विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बिलासपुर में जिला परिषद वार्डो के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन अधिसूचित

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियमए 1994 की धारा 89 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद वार्डों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन अधिसूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2026 के माध्यम से प्रारूप प्रकाशित कर 19 मार्च 2026 तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। परन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में जिला परिषद वार्डों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन अधिसूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद बिलासपुर में कुल 14 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। वार्ड संख्या 1 घण्डालवीं में ग्राम पंचायत भपराल, लन्जता, कोट, हटवाड़, देहरा.हटवाड, बम्म, पन्तेहड़ा, घण्डालवीं, मरहाणा, कुठेड़ा.मरहाणा, सलाओं.उपरली तथा हम्बोट सम्मिलित किए गए हैं। वार्ड संख्या 2 सेऊ में ग्राम पंचायत लैहड़ी.सरेल, बरोटा, डंगार, पडयालग, हरितल्यांगर, गतवाड़, गाहर, बाह, दधोल, छन्दोह, सेऊ, तड़ौन, कसारू तथा भराड़ी शामिल हैं। वार्ड संख्या 3 कुठेड़ा में ग्राम पंचायत मैहरी.काथला, लद्दा, तलवाड़ा, पटेर, कुठेड़ा, मोरसिंघी, दाबला, कोठी, तियूनखास, भल्सवाए तथा तल्याणा सम्मिलित हैं। वार्ड संख्या 4 ननावां में ग्राम पंचायत हवाण, कुहमझवाड़, सरयूनखास, ननावां, मल्यावर, रोहिण, बल्हचुराणी, हरलोग, घुमारवीं, दकड़ी, लुहारवीं, पट्टा तथा बाड़ी मंझेड़वा शामिल हैं। वार्ड संख्या 5 बड़गांव में ग्राम पंचायत बरठीं, मोही, पपलाह, पलासला, करलोटी, कपाहड़ा, छत, सण्डयार, कोटलूब्राह्मणां, आदि।

एलडीआर परीक्षा में सफल एसएमसी शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन 27 और 28 मार्च को

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुल्लू डा सुनील ठाकुर ने सूचित किया है कि निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के अनुसार, एलडीआर परीक्षा में सफल रहे एसएमसी शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस प्रक्रिया के तहत टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत और ड्राइंग मास्टर के पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। 27 मार्च को टीजीटी (हिंदी) और टीजीटी (संस्कृत) तथा 28 मार्च 2026 को ड्राइंग मास्टर दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, कुल्लू के कार्यालय में प्रात: 10:00 बजे से शुरू होगा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रमाणपत्रों सहित एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। टीजीटी (हिंदी/संस्कृत) हेतु मैट्रिक, 10+2, बीए/एमए अंकतालिका व डिग्री, बीएड (कंसोलिडेटेड मार्क्स शीट), टेट प्रमाण पत्र, एसएमसी नियुक्ति आदेश, एलडीआर आवेदन पत्र व एडमिट कार्ड, डीडीएसई द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र, कार्य एवं आचरण प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड एवं ड्राइंग मास्टर हेतु मैट्रिक, 10+2, संबंधित डिग्री/डिप्लोमा, एसएमसी नियुक्ति आदेश, एलडीआर आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र और हिमाचली बोनाफाइड लाना

प्रोडक्टिव एजिंग' कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिवसीय आजीविका उन्मुख कार्यशाला का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू। 23 से 29 मार्च 2026 तक जिला कुल्लू के ओल्ड एज होम, कलाथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'प्रोडक्टिव एजिंग' कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिवसीय आजीविका उन्मुख कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का शुभारम्भ वरिष्ठ नागरिक सुभाष मेहंदीरता, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त) द्वारा विधिवत रूप से किया गया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन के इस चरण में भी सीखने और

आत्मनिर्भर बनने के अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा इस प्रकार की पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होती है। यह कार्यशाला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का संचालन जिला कल्याण अधिकारी, कुल्लू द्वारा एसआरएलएम (स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन) आदि।

रामशहर के भियुंखरी स्कूल के बच्चों को एक्ट ह्यूमन फाउंडेशन की मदद से मिला नया भवन

शुभारंभ

फाउंडेशन की फाउंडर हरलीन कौर और उच्च शिक्षा विभाग सोलन के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने किया भवन का शुभारंभ

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। बुधवार का दिन रामशहर शिक्षा खण्ड के भियुंखरी स्कूल के लिए यादगार बन गया। आज राजकीय उच्च विद्यालय भियूँखरी के नए भवन का शिलान्यास हुआ। इस मौके पर इस स्कूल के लिए करीब 15 लाख धनराशि उपलब्ध करवाने वाली एक्ट ह्यूमन फाउंडेशन की फाउंडर हरलीन कौर, उच्च शिक्षा विभाग सोलन के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने मिलकर इस स्कूल के 2 नए कमरों का शिलान्यास किया। इससे पूर्व बैंड बाजे के साथ दोनों ही मुख्यातिथि का स्वागत अभिनंदन स्कूली बच्चों और ग्रामीणों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जहां अतिथियों का आदर सत्कार किया गया वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। फाउंडेशन की फाउंडर हरलीन कौर ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भविष्य में भी वे स्कूलों के बेहतर निर्माण, उच्च गुणवत्ता शिक्षा के लिए हिमाचल में काम करती रहेंगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग सोलन के उपनिदेशक गोपाल चौहान ने भी फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने जिस तरह से बच्चों की समस्या को देखते हुए 6 माह के भीतर स्कूल भवन को तैयार कर समर्पित किया है वो काबिले तारीफ है। बता दें कि साल 2018 में इस स्कूल को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया था

मिनी सचिवालय जोगिंदर नगर में आधार केंद्र का शुभारम्भ

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। उपमंडल के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत करते हुए एसडीएम जोगिंदर नगर श्री मनीश चौधरी द्वारा आज मिनी सचिवालय परिसर में आधार सेवा केंद्र का विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर एसडीएम मनीश चौधरी ने बताया कि अब क्षेत्र के लोगों को आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। इस नए केंद्र के माध्यम से नया आधार पंजीकरण, बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, पता (एड्रेस) संशोधन तथा आधार प्रिंट जैसी सभी सेवाएं नियमित रूप से मिनी सचिवालय में ही उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने बताया कि यह आधार केंद्र डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपमंडलाधिकारी (नागरिक) जोगिंदर नगर के अनुरोध पर स्वीकृत किया गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

एसडीएम ने क्षेत्रवासियों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि प्रशासन भविष्य में भी जनहित से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला मंडलों को बतौर प्रोत्साहन 2100 रुपये की सहायता राशि सीधे खातों में : सुनील शर्मा

आभार

नलवाड़ी मेले को राष्ट्रीय पहचान का दर्जा मिलने पर जताया आभार

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के जन्मदिवस के अवसर पर धारटटोह में महिला मंडलों के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र के करीब सौ महिला मंडलों की सदस्याएं भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान दस चयनित महिला मंडलों को 2100-2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिला मंडलों की सदस्याओं को कपड़े के सूट भी भेंट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला मंडलों को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब तक कई मंडलों को कुर्सियां, दरियां व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जा चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा 'देव दर्शन योजना' के तहत महिला मंडलों की सदस्याओं को विभिन्न शक्तिपीठों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। अब तक कई समूहों को माता नयनादेवी, ज्वालाजी और बगलामुखी के दर्शनों का अवसर मिल चुका है। सुनील शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों को फल एवं जूस भी वितरित किए जाएंगे। इसके बाद वह धारटटोह में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों, चुनौतियों के बीच किए गए कार्यों तथा आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनीष कुमार व अनुराग सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

क्रेच कार्यकर्ता व सहायिका के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। बाल विकास परियोजना सोलन के अंतर्गत क्रेच कार्यकर्ता तथा सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार प्रथम अप्रैल, 2026 को प्रातः 10.00 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन कविता गौतम ने दी। कविता गौतम ने कहा कि आंगनबाड़ी सह क्रैच केन्द आई.टी.आई. कॉलोनी के पर्यवेक्षक वृत्त सोलन शहरी, आंगनबाड़ी सह क्रैच केन्द थाना-2 नज़दीक डाईट के पर्यवेक्षक वृत्त सोलन शहरी तथा आंगनबाड़ी सह क्रैच केन्द रबौन के पर्यवेक्षक वृत्त सोलन ग्रामीण में क्रेच कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के 1-1 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को इन पदों के लिए 30 मार्च, 2026 सांय 05.00 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। क्रेच कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं व क्रेच सहायिकाओं के लिए उम्मीदवार की दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में उम्मीदवार को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा जारी एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ आयु, उच्च शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग, विधवा, स्टेट होम अथवा बालिका आश्रम की प्रवासिनी, तलाकशुदा, जिनके पति पिछले 07 वर्षों से लापता हो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन इन सभी प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ लानी होंगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अलग से व्यक्तिगत बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन में सम्पर्क कर सकते हैं।

सनावर की सैन्य विरासत पर पुस्तक का विमोचन

टीम एक्शन इंडिया
विशाल

कसौली। द लॉरेंस स्कूल, सनावर ने मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में आयोजित समारोह में अपनी कॉफी टेबल बुक 'the Lawrence School Sanawar Military Heritage 1847-2025' का विमोचन किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में एडमिरल विष्णु भागवत, एयर मार्शल के.सी. 'नंदा' करियप्पा, जनरल गौरव एस.जे.बी. राणा, मेजर जनरल ए.जे.एस. संधू, मेजर जनरल के.वी.एस. लालोटरा और मेजर जनरल (डॉ.) कुलप्रीत सिंह सहित कई गणमान्य पूर्व छात्र उपस्थित रहे। पैनल चर्चा में स्कूल की सैन्य परंपरा और नेतृत्व निर्माण में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। हेडमास्टर हिम्मत सिंह ढिल्लों ने परम वीर चक्र विजेता अरुण खेतरपाल को याद करते हुए कहा कि सनावर साहस, चरित्र और सेवा की जीवंत विरासत है।

कार्यक्रम का समापन स्कूल गीत और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

संक्षिप्त खबरें

आज का कार्यकर्ता डिजिटल और सामाजिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाला होना चाहिए : कृष्ण लाल चंदेल

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। संगठनात्मक सुदृढ़ता और वैचारिक मजबूती को केंद्र में रखते हुए जिला बिलासपुर में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत सभी 8 मंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों ने कार्यकर्ताओं के भीतर नई ऊर्जा और सक्रियता का संचार किया।

जिला अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल ने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व, विचारधारा और सेवा भाव को निखारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक मंडल में करीब 100 से 120 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने संगठन की जमीनी पकड़ को स्पष्ट रूप से दर्शाया। प्रशिक्षण सत्रों में बदलते समय के अनुरूप कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, जनसंपर्क के आधुनिक तरीकों और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आज का कार्यकर्ता डिजिटल और सामाजिक दोनों मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाने वाला होना चाहिए।

बिंदल का सरकार पर मेडिकल कॉलेज का स्थान बदलने पर तीखा हमला

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे 'घोषणावीरों की टोली' करार दिया है। बुधवार को नाहन में आयोजित एक तल्ख प्रेस वार्ता के दौरान बिंदल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल दागते हुए कहा कि सत्ता के 40 महीने बीत जाने के बाद अब मेडिकल कॉलेज के लिए नया स्थान चुनना महज एक राजनीतिक पैंतरा और जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो स्थान चयन का यह ड्रामा जनवरी 2023 में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर साढ़े तीन साल तक सिरमौर की जनता का कीमती वक्त बर्बाद किया। बिंदल ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जिस सरकार ने सत्ता संभालते ही बदले की भावना से स्कूल, तहसीलें, पटवार सर्किल और वेटरनरी अस्पताल बंद करने में मिनट भर की देरी नहीं की, उसे मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तलाशने में साढ़े तीन साल कैसे लग गए। डॉ. बिंदल ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कॉलेज निर्माण में 5 से 7 साल लगने की बात कही थी। बिंदल ने कहा कि यह स्वीकारोक्ति खुद सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि यदि काम समय पर शुरू होता तो आज नाहन का संस्थान भी चंबा और हमीरपुर की तरह अपनी मंजिल के करीब होता। बजट के मकड़जाल को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बजट को 3500 करोड़ से घटाकर 2868 करोड़ करना इस बात का सबूत है कि सरकार के पास निर्माण के लिए फूटी कौड़ी नहीं है और वह केवल वेतन बांटने वाली सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नर्सिंग कॉलेज के 70 करोड़ रुपये का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसे अपनी बजट बुक में तो सजा लिया,

चौथे वार्षिक स्नो टेल्स कार्यक्रम का सफल आयोजन,इंसानों और कुत्तों का अनोखा संगम

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पशु कल्याण के समर्थन में देश का सबसे बड़ा स्नो शो मनाली स्ट्रेज़ ने स्नो मैराथन लीग के सहयोग को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सेथन में चौथे वार्षिक स्नो टेल्स कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस आयोजन में कुत्तों और उनके मानव साथियों ने भाग लेकर करुणा, समुदाय और पशु कल्याण का एक सुंदर संदेश दिया।इस वर्ष 24 कुत्तों और उनके मानव साथियों ने डॉग-ह्यूमन स्नो रेस में भाग लिया। हम्पटा वैली के किनारे बसे सेथन के बर्फ से ढके मनमोहक दृश्य इस आयोजन के दौरान जीवंत हो उठे, जहां उत्साहित कुत्तों की भौंक और प्रतिभागियों के जोश से पूरा माहौल गूंज उठा। इस अनोखी रेस में भाग लेने के लिए देशभर से प्रतिभागी पहुंचे, जिनमें कुछ लोग मुंबई से भी आए।स्नोटेल्स अब एक लोकप्रिय वार्षिक आयोजन बन चुका है और यह कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति जिलों में मनाली स्ट्रेज़ के कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

अल्पसंख्यक, दिव्यांग और कल्याण योजनाओं पर समीक्षा बैठक : प्रियंका वर्मा

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। नाहन में उपायुक्त प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जिला स्तर पर संचालित योजनाओं की स्थिति, लाभार्थियों तक पहुंच और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई बैठक में बताया गया कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी लगभग 10 प्रतिशत है। जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। निर्धारित अवधि के दौरान 34 लाभार्थियों को 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपये की राशि सरल ऋण के रूप में प्रदान की गई है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है।

एकीकृत आवास कार्यक्रम और शहरी नवीनीकरण योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद को स्लॉटर हाउस के क्रियान्वयन, मांस की दुकानों के नियमित निरीक्षण और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जा सके। बैठक में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति और स्थानीय स्तरीय समिति से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। 'सिपड़ा' योजना के तहत सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही प्रत्येक सरकारी संस्थान में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने पर भी जोर दिया गया। दिव्यांग जनों के लिए संचालित योजनाओं के तहत 102 विद्यार्थियों को लगभग 12 लाख 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के तहत 18 लाभार्थियों को 6 लाख 50 हजार रुपये की सहायता दी गई। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत जिला में कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत अब तक 208 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मैनुअल स्कैवेंजिंग उन्मूलन और अन्य सामाजिक योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर भी समीक्षा की गई। बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने किया।

रोटरी क्लब की पहल से नाहन विद्यालय के रसोईघर का मरम्मत कार्य शुरू

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। रोटरी क्लब नाहन द्वारा जिला प्रशासन, सिरमौर के सहयोग से पी.एम. श्री राजकीय उत्कृष्ट राजमाता मन्दिरा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाहन (हि.प्र.)में मिड-डे मील रसोईघर की मरम्मत एवं शेड निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में रसोईघर की स्थिति को सुधारने के लिए यह कार्य लंबे समय से आवश्यक था, जिसे अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण में मिड-डे मील उपलब्ध कराना है। अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (ष्टस्क्र) के तहत किया जा रहा है और इसमें शीला फोम, कालाअम्ब स्थित उद्योग इकाई का सहयोग सराहनीय है। रोटरी क्लब नाहन ने इस कार्य के लिए लगातार प्रयास किए और जिला प्रशासन के सहयोग से इसे शुरू करवाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब नाहन सदैव शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहा है और आगे भी ऐसे जनहित कार्यों को प्राथमिकता देता रहेगा।

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान: उपायुक्त

एसपी जैरथ

नाहन। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज उद्योगपतियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया यहां डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें उद्योगपतियों ने उनके सामने पेश आ रही समस्याओं को रखा । मीडिया से बात करते हुई डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि उद्योगपतियों द्वारा बैठक रखने का आग्रह किया गया था और इस बैठक में उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया है जिससे उद्योगपतियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंठ्ने कहा कि

भालारिहड़ा में शुरू हुए मां शारदा के दो दिवसीय मेले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर। बुधवार को ग्राम पंचायत मैन भरोला के भालारिहड़ा में मां शारदा के दो दिवसीय मेलों का शुभारंभ हुआ। मेले का शुभारंभ देव पशाकोट कुट खेतडू़ की जलेब के साथ हुआ। मेले के शुभारंभ समारोह में समाजसेवी व ग्राम पंचायत रोपड़ी कलैहडू के पूर्व प्रधान अजय बरवाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। मेला कमेटी के प्रधान संजय जमवाल ने मुख्यातिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मेले के दौरान स्थानीय पाठशाला भालारिहड़ा के बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पेश किए गए। स्कूली बच्चों ने नशे के दुष्प्रभावों पर एक नाटक प्रस्तुत किया

Government of Himachal Pradesh
Jal Shakti Vibhag

"Notice Inviting e-Tender"

The Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Flood Protection Division, Gagret (HP) invites online e-tender on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following works through online process :-

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender document	Time Limit	Eligible Class of Contractor
1	Providing Flood Protection work to Chatara khad to protect the Labana Mohalla in Village Chatara in Tehsil & Distt . Una (HP) (SH:- C/O wire Crated wall/ Gabion wall including wire create apron etc. from RD 8200/11600 to 8200/11825 on left side of Chatara Khad to protect the cultivated land and abadies in village Chatara in Gilbadi Mohalla).	Rs. 38,84,647/-	Rs. 77,693/-	Rs. 2000/-	3 (Three) Months	Class "D"
	Swan River Flood Management Project Phase-IV in Distt . Una (HP) Emergent work for Repair and Maintenance in Fatehpur –IInd Khad/ Jhundowal Khad. (SH:- C/O 42 mtr long earthen embankment including wire created Apron and stone pitching from RD 8200/2450 to 8200/2492 in place of washed portion of existing embankment on left side of Fatehpur IInd Khad in Village Jhundowal to protect the cultivated land & Abadies.	Rs. 9,91,195/-	Rs. 19,824/-	Rs. 350/-	3 (Three) Months	Class "D"
	Swan River Flood Management Project Phase-IV in Distt . Una (HP) Emergent work for Repair and Maintenance in Fatehpur –IInd Khad. (SH:- C/O 28 mtr long earthen embankment including wire created Apron and stone pitching from RD 8200/5865 to 8200/5893 in place of washed portion of existing embankment on left side of Fatehpur IInd Khad in Village Badehar/Behdala to protect the cultivated land & Abadies	Rs. 7,99,384/-	Rs. 15,988/-	Rs. 350/-	3 (Three) Months	Class "D"

1. The last date of physically submission of earnest money deposit and cost of tender documents etc. on 04.04.2026 upto 12:00 PM.
2. The last date of e-tendering upto 04.04.2026 at 12:00 PM and the same will be opened on the day on 04.04.2026 at 12:30 PM.
3. The Tender forms and other detailed conditions can be downloaded from the http://hptenders.gov.in.

RO No. 7415/2025-2026
HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

नाहन नगर परिषद के 06 वार्ड महिलाओं के लिए होंगे रिजर्व : एसडीएम

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। नाहन परिषद के 13 वार्डो में 6 वार्डों को महिलाओं के रिजर्व किये जाने की प्रक्रिया 28 मार्च को तय कर दी गई है। इस बाबत एसडीएम एंव उपमंडल निर्वाचन अधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 की अधिसूचना संख्या एस0ई0सी0 एच पी एफ0002 (01) /1/1/2021-1-7324 -दिनांक 24-03-2026 के आदेशों अनुसार नाहन नगर परिषद के 13 वार्डो में से एक वार्ड अनुसूचित वर्ग की महिला हेतु तथा शेष अन्य में से 5 वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित किये जाने हैं। एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने बताया कि नाहन नगर परिषद के उक्त वार्डो के आरक्षण का निर्धारण दिनांक 28.03.2026 को सांय 12:30 बजे नगर परिषद के टाउन हॉल में लॉट द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में नगर परिषद के पार्षद रहे व अन्य सम्बंधित लोग शामिल होंगे। गौरतलब है कि 13 वार्डो में से 6 वार्डो को आरक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाने की प्रक्रिया से शहर के कई कांग्रेस - भाजपा के पार्षद रहे व अन्य छन6लड़ने वाले इच्छुक नेताओं की सांसे अटकी है। कुछ महीने पहले भी लाटरी के माध्यम महिलाओं के लिए रिजर्व हुए वार्डो के पार्षदों का।चुनावी समीकरण गड़बड़ा गया था। अब एक बार फिर से वार्डो का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होने जा रहा है।अब देखना यह है कि किन नेताओं के चुनाव पर ब्रेक लगेगी और किनको यह महिला आरक्षण राहत देगा अपने वार्ड से चुनाव लड़ने की।

हृदय रोग से पीड़ित सुशील हुआ स्वास्थ्य, अभिभावकों ने रोटरी क्लब का आभार जताया

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन। हृदय की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मासूम सुशील के लिए अब नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में सफल उपचार के बाद सुशील अब पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर नाहन लौट आया है। इस अवसर पर डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने मासूम सुशील को गोद में उठा कर दुलार किया। वर्तमान में सुशील सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है और पहले की तरह अपनी दिनचर्या में लौट आया है। जानकारी के अनुसार, सुशील को हृदय में ब्लॉकेज की गंभीर समस्या थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने तत्काल उपचार और सर्जरी की सलाह दी थी। सुशील के पिता जग्गिया राम, जो पेशे से मिस्त्री हैं, सीमित आय के कारण इस महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे कठिन समय में परिवार के सामने अपने बच्चे के जीवन को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई थी। इसी दौरान रोटरी क्लब नाहन ने मानवता और सेवा भाव का परिचय देते हुए आगे आकर परिवार की सहायता की। क्लब द्वारा ?51,000 की आर्थिक मदद प्रदान की गई, जिससे सुशील के उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। रोटरी क्लब के इस सहयोग ने न केवल आर्थिक संबल दिया, बल्कि परिवार को मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान की। रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष मनीष जैन ने इस अवसर पर कहा कि सुशील को नया जीवन मिलना क्लब के लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि रोटरी का मूल उद्देश्य 'स्द्गह्म1द्बष्द्ग ड्डड्ढश1द्ग स्द्गद्यद्घ' यानी 'स्वयं से ऊपर सेवा' है, और क्लब इसी भावना के साथ समाज के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

संपादकीय

प्राकृतिक संसाधनः सृष्टि की साझा धरोहर

पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जल, वायु, वन, खनिज, मिट्टी, जीवझ्रजंतु और ऊर्जा स्त्रोत मानवता की निजी संपत्ति न होकर संपूर्ण सृष्टि की साझा धरोहर हैं। यह विचार केवल नैतिक आग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास, जैविक विकास और आधुनिक वैज्ञानिक समझ का गहन निष्कर्ष है। विज्ञान स्पष्ट करता है कि जिन ऊर्जा स्त्रोतों पर आधुनिक सभ्यता आधारित है, वे मानव जीवन की समय-सीमा में पुनः निर्मित नहीं हो सकते। पेट्रोलियम को बनने में पांच से 30 करोड़ वर्ष, कोयले को तीन से 40 करोड़ वर्ष और प्राकृतिक गैस को करोड़ों वर्षों का समय लगता है। पृथ्वी की विशाल प्रयोगशाला ने जिन्हें युगों में निर्मित किया, उन्हें मनुष्य यदि कुछ वर्षों के युद्ध, संघर्ष या लालच में नष्ट कर दे, तो यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से मूर्खता है बल्कि नैतिक रूप से भी गंभीर अन्याय है। भारतीय चिंतन इस सत्य को प्राचीन काल से ही स्वीकार करता आया है। अथर्ववेद में कहा गया है माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि पृथ्वी के उपहार किसी एक समाज, राष्ट्र या पीढ़ी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समस्त जीव जगत के लिए समान रूप से हैं। उपनिषद का वाक्य ईशावास्यमिदं सर्वं इसी भावना को और व्यापक बनाता है। यह सम्पूर्ण जगत किसी का निजी स्वामित्व नहीं, बल्कि साझा अस्तित्व है। आधुनिक भाषा में इसे वैश्विक साझा संसाधन कहा जा सकता है, जहाँ संसाधन किसी के स्वामित्व में नहीं बल्कि सबके उपयोग के लिए होते हैं। इसी आधार पर प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार का विचार मूलतः अमानवीय है। मनुष्य अधिकतम स्वयं को इन संसाधनों का संरक्षक और न्यासी कह सकता है। उसके पास उपयोग का अधिकार है, स्वामित्व का नहीं। एक न्यासी संसाधनों का संरक्षण करता है, उनका विनाश नहीं करता। वर्तमान विश्व व्यवस्था ने इस मूलभूत सत्य को पीछे छोड़ दिया है। देखा यह जा रहा है कि जो संसाधन मानवता की सामूहिक धरोहर थे, वे अब संपत्ति, राजनीतिक शक्ति, भू रणनीतिक हथियार और औद्योगिक लाभ के साधन बन गए हैं। पश्चिम एशिया में तेल कुओं पर हमले, रूस यूक्रेन संघर्ष में गैस पाइपलाइन का टूटना या अफ्रीका में खनिज क्षेत्रों को लेकर गृहयुद्ध, ये सभी घटनाएँ केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव डालती हैं। तेल महंगा होता है, परिवहन लागत बढ़ती है, बिजली दरें ऊँची होती हैं और खाद्य संकट गहराता है। अंततः सबसे अधिक पीड़ा उस सामान्य जन को झेलनी पड़ती है जिसने न युद्ध किया और न संसाधनों का दुरुपयोग किया। यह वैश्विक अन्याय का विकृत स्वरूप है। प्राकृतिक संसाधनों की हानि केवल आर्थिक संकट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी प्रभावित करती है। एक जंगल के कटने से वर्षा चक्र, मिट्टी की उर्वरता, जल संचयन और वन्य जीवन सब प्रभावित होते हैं।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

ईरान का अपराधः संप्रभुता का साहस और अमेरिकी हेजमनी को चुनौती

प्रसांत वीर सिंह

> "गैस संकट से उपजी स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ बेईमान तत्व सिलेंडरों को काला बाजार में बेच रहे हैं, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अब तक 3500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं और करीब 1400 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने 2000 से ज्यादा पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियां पर अचानक जांच भी की है, ताकि सप्लाई सुचारू बनी रहे"

ईरान-अमेरिका संघर्ष का वास्तविक कारण क्या है, यह समझने के लिए सीधे कहानी पर जाने की बजाय अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हेजमनी अर्थात वर्चस्व अथवा सरल शब्दों में दादागिरी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के संदर्भ में, अमेरिकन हेजमनी को पैक्स अमेरिकाना संबोधित किया जाता है, जो वास्तव में इस विचार पर आधारित है कि अमेरिका अपनी आर्थिक, सैनिक और संस्थागत शक्तियों के बल पर विश्व को अपनी शर्तों पर चलने के लिए विवश करता है या दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी शक्ति के बल पर अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक व्यवस्था को नियंत्रित करता है; और फिर वह अपने इस आक्रामक वर्चस्ववादी सोच को वैश्विक शांति और उदार लोकतंत्र का आदर्शवादी मुखौटा लगाकर दुनिया के सामने रखता ताकि वह स्वयं को इस प्रकार दिखा सके कि वैश्विक शांति स्थापित करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, अन्यथा विश्व व्यवस्था असंतुलित हो जाएगा, वैश्विक हितों का नुकसान होगा।

इसके विरोध में जब कोई देश इस व्यवस्था से टकराता है तो, या तो वहाँ की सरकार बदल दी जाती है अर्थात येन केन प्रकारेण रिजीम चेंज कर दिया जाता है (एक सामान्य उदाहरण के तौर पर इसे हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में क्रांति के कारण हुए सत्ता परिवर्तन से समझ सकते हैं), या फिर उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और वास्तव में थोड़ी गहराई से देखा जाए तो ईरान के साथ ये दोनों ही हुए हैं। जबकि मुख्यधारा की मीडिया ईरान के परमाणु कार्यक्रम, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और शिया इस्लाम के विस्तार को वर्तमान संघर्ष का कारण बताती है, जो केवल अमेरिका प्रायोजित एक सतही और सुविधाजनक मुखौटा है। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य पूर्व सीआईए निदेशक की वह स्वीकारोक्ति है, जिसमें वे कहते हैं कि ह्लमुद्दा कभी परमाणु हथियारों का नहीं था, मुद्दा सदैव यह था कि फारस की खाड़ी को नियंत्रित कौन करता है ह्व असल में जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों, ऊर्जा अर्थव्यवस्था सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बहुआयामी दृष्टिकोण से इस मुद्दे को समझते हैं, तब स्पष्ट तौर पर यह परिलक्षित होता है कि यदि आप रूस, चीन इत्यादि देशों जैसे आर्थिक और तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आपको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपनी संप्रभुता वाशिंगटन डीसी के पास गिरवी रखनी पड़ेगी अन्यथा इराक और ईरान जैसे देश आपके सामने हैं।

ईरान के प्रति पश्चिमी देशों के रवैये को समझने के लिए हमें वर्ष 1951 में जाना होगा। जब ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक द्वारा, ईरान का तेल, ईरान का हक, तर्क के साथ उस एंग्लो-ईरानी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके, ईरानी तेल पर ईरान का हक स्थापित कर दिया गया, जिसके सबसे बड़े शेयर धारक ब्रिटिश थे, यह पश्चिमी हेजमनी के लिए पहला बड़ा झटका था। इससे क्रुद्ध होकर संयुक्त रूप से, यूनाइटेड किंगडम की खुफिया एजेंसी एमआई सिक्स और अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए ने ऑपरेशन एजेक्स के अंतर्गत वर्ष 1953 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मोहम्मद मोसाद्देक सरकार का तख्तापलट कर दिया और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ब्रिटिश एवं अमेरिकी हितों (मुख्यतः तेल अर्थव्यवस्था) के अनुरूप गद्दी पर बैठाया। यह आधुनिक इतिहास में रिजीम चेंज का पहला संगठित उदाहरण था, जिससे ईरान का लोकतांत्रिक प्रयोग समाप्त हो गया और शाह (राजा) की तानाशाही पुनः स्थापित हो गई। इधर ईरानी शाह भी अपनी गुप्त पुलिस सावक के अत्याचारों के बल पर, जिसने हजारों राष्ट्रवादी ईरानियों को अपना शिकार बनाया, लगभग अगले ढाई दशक तक ईरान में अमेरिका के पुलिसमैन बने रहे। इस दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था डिपेंडेंसी थ्योरी का सटीक उदाहरण बनी, जहाँ ईरान एक पेरिफेरल स्टेट था, जो अपने संसाधनों को कोर स्टेट्स (पश्चिमी देशों) को सस्ते में दे रहा था और बदले में उनके महंगे हथियार और पश्चिमी विचारधारा का आयात कर रहा था। मोसाद्देक सरकार का तख्तापलट और ईरान का पेरिफेरल स्टेट बनना, वह टर्निंग प्वाइंट था, जिसने ईरानी समाज में अमेरिका के प्रति गहरी नफरत पैदा कर की। अब वक्त वर्ष 1979 का आता है, जब अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में, बढ़ते सामाजिक-आर्थिक असंतोष, पश्चिमीकरण और शाह के तानाशाही शासन के विरोधस्वरुप धार्मिक राष्ट्रवाद से प्रेरित इस्लामी क्रांति द्वारा, जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिमी समर्थक राजशाही को समाप्त कर दिया, इस असंतोष को मूर्त रूप दिया गया और ईरानी जनता के जनमत संग्रह के समर्थन से अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान को एक शिया इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया, जो खुले तौर पर अमेरिका विरोधी विचारधारा पर आधारित था। यह केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि पश्चिमी आधुनिकता और आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक सभ्यतागत विद्रोह के साथ-साथ पैक्स अमेरिकाना को पहला चुनौती भी था, क्योंकि इस्लामी क्रांति के साथ सर्वोच्च नेता बनते ही खुमैनी ने पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के प्रति अधीनस्थता की नीति को नष्ट करते हुए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पेट्रो-डॉलर प्रणाली के आर्थिक ढांचे को खारिज कर दिया, जो वैश्विक तेल व्यापार हेतु अमेरिकी डॉलर पर निर्भर था, और अन्य मुद्राओं में व्यापार शुरू करके सीधे तौर पर डॉलर की वैश्विक मांग और अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व पर प्रहार किया। परिणामतः खुमैनी के इस राष्ट्रवादी कदम ने ईरान और अमेरिका के मध्य अगले कई दशकों तक चलने वाली तनाव की नींव रखी।

इसी बीच दूसरी ओर, पड़ोसी मुल्क इराक (तत्कालीन सद्दाम हुसैन) ईरान में हुए शिया इस्लामी क्रांति से भयभीत हो गया कि कहीं यह विचारधारा इराक के बहुसंख्यक शिया आबादी को आंदोलित करके उसके सुन्नी-नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर न कर दे। अंततः सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने ईरान के शिया प्रभाव को रोकने (शत्त अल-अरब जलमार्ग पर पूर्ण नियंत्रण और ईरान के तेल-समृद्ध खुजेस्तान प्रांत को हथियाने) के लिए वर्ष 1980 में युद्ध (वर्ष 1980 से वर्ष 1988 तक) शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच स्थायी दुश्मनी पैदा हो गई। ईरान-इराक युद्ध के दौरान, अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के लिए इराक को हथियार और खुफिया जानकारी दी ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके, जिसमें सद्दाम हुसैन को रासायनिक हथियारों के उपयोग में अप्रत्यक्ष मदद भी शामिल थी। हालाँकि बाद में, अमेरिका ने वैश्विक शांति और उदार लोकतंत्र का अपना आदर्शवादी मुखौटा बचाए रखने के लिए, जनसंहार के हथियारों के उपयोग का आरोप लगाकर इराक पर आक्रमण किया और अंततः सद्दाम हुसैन को भी निपटा दिया।

वर्तमान में जब ईरान-अमेरिका का भयावह संघर्ष जारी है, तब हमें बताया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन क्या आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं? वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के बाद, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कम से कम 10 से अधिक बार पुष्टि की, कि ईरान समझौते की हर शर्त का पालन कर रहा है।

साथ ही साथ ईरान परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता भी है और नियमित निरीक्षण भी कराता है। जबकि इसके विपरीत इजरायल, जिसके पास अनुमानतः 80 से 400 परमाणु हथियार हैं, ने न तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है और न ही वह किसी अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देता है। फिर भी, प्रतिबंध केवल ईरान पर हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य एशियाई देशों ने भी परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता के चलते आज वे वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा हैं। जबकि ईरान अमेरिका के निशाने पर है, क्योंकि ईरान का कसूर परमाणु तकनीक नहीं, बल्कि उसकी वह राजनीतिक विचारधारा है, जो मध्य-पूर्व में अमेरिकी हितों के आड़े आती है। इसके साथ-साथ कई बार अमेरिका ने ईरान पर ऐसे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जो कभी किसी अन्य देश पर नहीं लगे। हाल ही में अमेरिका ने अधिकतम दबाव अभियान के तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों एवं उनकी कंपनियों को भी निशाना बनाया, जिसमें भारत और चीन सहित कई बड़े देश भी शामिल हैं। विशेष रूप से, अमेरिका ने स्वीफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को बाहर कर दिया, जिससे ईरान का अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप हो गया। हालाँकि, तब भी ईरान के तेल निर्यात पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी।

कुल मिलाकर, उक्त घटनाक्रम बताते हैं कि शक्तिशाली के सामने निर्दोष होना भी अपराध होता है। अंततः ईरान का अपराध न तो परमाणु कार्यक्रम है,

न ही आतंकवाद और न ही शिया विस्तार, बल्कि ईरान का अपराध यह है कि उसने अमेरिकी हेजमनी को चुनौती दी, उसने कहा हमारा तेल, हमारी मुद्रा, हमारा निर्णय, जिसके लिए ईरान को पिछले साढ़े चार दशक से दंडित किया जा रहा है।

चंडीगढ़ः नाम बड़े दर्शन छोटे

निर्मल रानी

भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ अकेला है जिसे ह्लसिटी ब्यूटीफुलह्व कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि यह देश का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो देश के पंजाब और हरियाणा जैसे दो समृद्ध राज्यों की संयुक्त राजधानी है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ न केवल एक शहर है, बल्कि यह एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश भी है, जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसकी स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि 1947 के भारत विभाजन के बाद जब पूर्वी पंजाब की पुरानी राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गयी तो भारतीय पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई।उसी समय 1950 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप चंडीगढ़ को आधुनिक भारत के पहले व पूर्णतः नियोजित शहर के रूप में पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बनाया गया। इसे विश्व प्रसिद्ध स्विस-फ्रेंच वास्तुकार ले कोर्बुजिए ने डिजाइन किया था। बाद में जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित कर हरियाणा बनाया गया उस समय चंडीगढ़ को दोनों राज्यों के बीच विवाद से बचने के लिए केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और इसे दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। आज भी दोनों प्रदेशों की राजधानी होने के बावजूद चंडीगढ़ न तो पूरी तरह पंजाब का है और न हरियाणा का बल्कि यह पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित है। लगभग 50 आयताकार सेक्टरों में बांटा गये इस चंडीगढ़ में चौड़ी सड़कें, हरियाली, पार्क और आधुनिक इमारतें हैं। यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के रूप में विधानसभा, सचिवालय व उच्च न्यायालय हैं। यहाँ विद्युत ,जल निकासी,नाले नालियां सभी भूमिगत हैं। यह शहर यूनेस्को की भी विश्व धरोहर है।यहाँ स्थित रॉक गार्डन, सुखना झील, रोज गार्डन आदि जगहें इसे पर्यटन स्थल के रूप में पहचान देती हैं। भारत के अन्य शहरों की तुलना में यहां जनघनत्व कम, सड़कें व्यवस्थित और प्रदूषण नियंत्रित होने का दावा किया जाता है। यह भारत में मानव विकास सूचकांक और जीवन की गुणवत्ता में भी शीर्ष पर है। यह ह्लपेंशनर्स पैराडाइजह्व भी कहलाता है क्योंकि यहां शांत वातावरण, अच्छी सुविधाएं और उच्च जीवन स्तर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में यह दूसरे नंबर पर था । आवासीय क्षेत्र, बाजार , जल निकासी और सार्वजनिक शौचालयों के मामले में भी यह सबसे साफ केंद्र शासित प्रदेश गिना जाता है। परन्तु इसी चमचमाते चंडीगढ़ का एक दूसरा पहलू भी है जो कि अत्यंत दुखद,शर्मनाक व चंडीगढ़ जैसे सुनियोजित शहर की सुंदरता व इस पर लगे सिटी ब्यूटीफुल के लेबल पर सवाल खड़ा करने वाला है।

मिसाल के तौर पर निश्चित रूप से यहाँ के अधिकांश मुख्य मार्ग साफ सुथरे हैं परन्तु जब आप चंडीगढ़ के घनी आबादी वाले रिहाइशी इलाकों से गुजरें तो आप को पता चलेगा कि चंडीगढ़ की एक बड़ी मध्यम व निम्न मध्यम वर्गीय आबादी किस तरह रहती है।

विचार

25 दिन, 200 अरब डॉलर, हजारों मौतें और खाड़ी देशों का पानी खतरे में

ओंकारेश्वर पांडेय

युद्ध छेड़ने के 25 दिन के भीतर अमेरिका अब ईरान के साथ बातचीत पर आ गया है। पाकिस्तान उस बातचीत की मेजबानी करने का दावा कर रहा है। युद्ध का एक महीना भी नहीं गुजरा और बातचीत की बात करना दुनिया के तमाम शांति पसंद मुल्कों के लिए सुखद संकेत होता। मगर ईरान की ओर से मिल रहे संकेत तत्काल युद्ध समाप्त होने के संकेत नहीं देते और बातचीत की इच्छा जताना अपने आप में दशार्ता है कि अमेरिका इस युद्ध में थक गया है या वह उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाया, जिसके लिए युद्ध में उतरा। अगर बातचीत ही करनी थी, तो पिछली बातचीत के बीच हमले का कोई औचित्य नहीं था।

बात रणनीति की है,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान मीडिया में छाया है कि इस युद्ध के लिए उनके रक्षा सचिव पीट हेगसेठ ने कहा था- लेट्स डू इट। पिछले ही हफ्ते अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट ने इस युद्ध के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए इस्तीफा दे दिया था और अब ट्रंप का पांच दिवसीय युद्ध विराम और शांति समझौते की बात करना कई सवाल खड़े करता है।

अमेरिका ने ईरान पर हमले और युद्ध विराम के संदर्भ में जो भी कहा हो, पर उससे इतर ईरान ने इस बार युद्ध को अपनी सभ्यतागत अस्तित्व और साख की लड़ाई मान ली है,इसलिए युद्ध समाप्त होने में समय लगेगा।

और जब भी युद्ध समाप्त होगा, तो ईरान, इजराइल और अमेरिका को निश्चय ही इस युद्ध में हुए ध्वंस का पुनर्निर्माण करने में दशकों लगेंगे। पर जो नैतिकता और साख का ढांचा टूट गया है, उसको बनाने में सदियां लगेंगी। सत्य कहां है? तथ्य कहां है? सबूत कहां है? झूठ सागर में डूबता जा रहा। यह सेंचुरियन ब्लंडर है। सदी की भूल। यह सदी की त्रासदी है और सदी का सबक भी। अब सागर के भीतर से नयी विश्व-व्यवस्था की सुनामी उठ रही है। दुनिया अब उस मोड़ पर है, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, और ईरानी सैन्य कमांडर उन्हें उन्हीं की भाषा में 'यू आर फायर्ड' कह रहे हैं। जब अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के सभी ऊर्जा ढांचों को नेस्तनाबूद कर देगा, तो ईरान ने जवाब दिया कि ठीक है, वह तब तक के लिए हार्मूज की खाड़ी को बंद करके रखेगा, जब तक कि उन ढांचों का पुनर्निर्माण न हो जाय। बस इसी बयान ने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया और वे शांति वार्ता की बात करने लगे।

अगर बारीकी से देखें तो यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह रणनीति का अंतिम संस्कार है, जहाँ दोनों पक्ष पानी, बिजली और स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, और विश्व समुदाय इस आत्मघाती नाटक के सबसे कड़वे फल भोग रहा है। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट है कि अब तक ईरान की 82 हजार से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान इजराइल में भी काफी हो रहा है।

अनेक विश्लेषक इस युद्ध को 'बहुध्रुवीय व्यवस्था' के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन वे उस मूल सत्य को नजरअंदाज कर रहे हैं जो अब हर गली, हर ड्रोन हमले, और हर अल्टीमेटम में झलक रहा है। यह युद्ध कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक बड़े घोटाले को छुपाने का सस्ता नाटक है।

पेंटागन ने स्वीकार किया है कि ईरान पर हमले के पहले सप्ताह में ही अमेरिका ने लगभग 110 अरब डॉलर खर्च कर दिए। 24 मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 200 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। पेंटागन ने कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है । विशेषज्ञों का अनुमान है कि युद्ध की दैनिक लागत 1 से 2 अरब डॉलर के बीच है । यह रकम एक नए 'फोर्ड-क्लास' विमानवाहक पोत से भी अधिक है। डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि असली आंकड़ा 500 अरब डॉलर के पार जा सकता है। 25 दिन बीत चुके हैं।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, बल्कि नतंज सुविधा पर दोबारा हमला हुआ,ईरान ने दीमोना (इजराइल का परमाणु ढांचा) पर मिसाइल दागी।

अब अमेरिका को अपने ही सहयोगी देशों (यूएई, सऊदी अरब) की जलापूर्ति और बिजली घरों की सुरक्षा की चिंता सता रही है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआईः HPHIN / 2012 / 48072

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश-174303 से प्रकाशित एवं अर्थ प्रकाश प्रैस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर-29डी, चंडीगढ़ से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
स्थानीय संपादक : पंकज शर्मा (9418026789)
ई-मेल : actionindiashimla@gmail.com
actionindiauna@gmail.com

एक्शन इंडिया शिमला कार्यालयः किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001
एक्शन इंडिया ऊना कार्यालयः कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना, हिमाचल प्रदेश-174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

व्यंग्य

गैस संकट से निपटने के हों ठोस उपाय

रोहित माहेश्वरी

खाड़ी देशों में चल रहे तनाव का असर अब भारत की गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। गैस संकट ने रसोई के बजट और ऊर्जा सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चुनौती और संकट बड़ा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना है। ये करीब 167 किमी लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20 फीसदी हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50 फीसदी कच्चा तेल और 54 फीसदी एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। गैस-तेल संकट पर पीएम मोदी ने संसद में कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। लेकिन जमीनी हालात देखें तो ऐसा आभास होता है कि सरकार जो बता रही है, वो आधा सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। दिलचस्मप बात यह है कि मोदी सरकार एक तरफ तो किसी तरह का संकट होने की बात से ही इनकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर वे यह भी कह रहे हैं कि, "जिस तरह भारत से कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए संकट से उबरा था, उसी तरह एलपीजी के संकट से भी उबर जाएगा।" सवाल है कि जब आप संकट मान ही नहीं रहे हैं तो फिर किस संकट से उबरने की बात कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि अगर सब कुछ ठीक है, गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में मेन कोर्स का खाना बनना क्यों बंद हो गया? अयोध्या में चलने वाली राम रसोई क्यों बंद हुई, जहां 25 हजार तीर्थयात्री प्रतिदिन निशुल्क भोजन करते हैं? स्वयं मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में 35 साल से तीर्थयात्रियों के लिए चल रही रसोई क्यों बंद है? भारतीय रेलवे अपनी कैटरिंग सर्विस क्यों सीमित करने की तैयारी कर रहा है?

स्मार्ट-मौनऔर सन्नाटे का कोटा

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

महुआ टोला गांव में जब 'झपटल बाबू' ने प्रधानी का पर्चा भरा, तो उन्होंने शोर-शराबे वाली राजनीति को ही अपना निशाना बना लिया। उनका नया चुनावी मुद्दा था–'डिजिटल मौन और ध्वनि-मुक्ति अभियान'। झपटल बाबू का तर्क था कि गांव की सारी समस्याओं की जड़ सड़क या पानी नहीं, बल्कि 'अनावश्यक बोलना' है। उन्होंने घोषणा की कि जीतते ही वे पूरे गांव में 'शांति-सेंसर' लगवाएंगे और जो व्यक्ति दिन भर में सबसे कम शब्द बोलेगा, उसे 'मौन-रत्न' की उपाधि के साथ मुफ्त राशन मिलेगा। उनका दावा था कि गांव वालों की बातों से जो ऊर्जा बर्बाद होती है, उसे वे एक 'साउंड-कैप्चर' मशीन से इकट्ठा करेंगे और उससे गांव की स्ट्रीट लाइटें जलेंगी। गांव के लोग, जो अब तक चौपाल पर बैठकर दिन भर लफ्फाजी करते थे, अचानक इस 'खामोश क्रांति' के पीछे ऐसे दीवाने हुए कि उन्हें अपनी जबान ही बोझ लगने लगी।

प्रचार के अंतिम सप्ताह में झपटल बाबू ने गांव के बरगद के पेड़ पर एक पुराना और खराब हो चुका माइक्रोवेव टांग दिया और उसे 'ब्रह्मांडीय ध्वनि अवशोषक' घोषित कर दिया। उन्होंने गांव वालों को पट्टी पढ़ाई कि यह मशीन केवल उन्हीं की दुआएं सुनेगी जो झपटल बाबू को वोट देने का संकल्प 'मन ही मन' लेंगे। विपक्षी उम्मीदवार 'गपोड़ी लाल' चिल्ला-चिल्लाकर विकास के वादे कर रहे थे, लेकिन झपटल बाबू ने उन्हें 'ध्वनि प्रदूषक' करार देकर जनता की नजरों में गिरा दिया। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया; लोग इशारों में बात करने लगे और घरों में रेडियो तक बजना बंद हो गया। झपटल बाबू ने एक रजिस्टर बनवाया जिसमें 'मौन-अनुयायियों' के नाम लिखे गए, और जनता को लगा कि बस, अब बिना कुछ बोले ही स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा और गांव 'साइलेंट स्मार्ट विलेज' बन जाएगा। जिस दिन चुनाव का परिणाम आया और झपटल बाबू की ऐतिहासिक जीत हुई, पूरा गांव अपना 'मौन-पुरस्कार' और शांति का लाभ लेने उनके दरवाजे पर जमा हुआ। लोग चुपचाप खड़े थे, उम्मीद में कि अब कोई बड़ा चमत्कार होगा।

रियल एस्टेट की कंपनी एम्मार के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के केस में हाई कोर्ट का दखल देने से इंकार

- हाई कोर्ट ने कहा, जमीन के सौदे में तथ्य छिपाना केवल सिविल विवाद नहीं, आपराधिक मामला भी
- गुरुग्राम की अदालत के एफआइआर के आदेश को बरकरार रखा, एम्मार ने सिनर्जी फिनहब को धोखे में रखकर कराया निवेश

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट की कंपनी एम्मार इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की एफआइआर को रद्द करने से इंकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यापारिक समझौते में जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है तो उसे केवल दीवानी (सिविल) विवाद मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद एम्मार इंडिया और उसके उन अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट के व्यापारिक समझौते में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का काम किया है। एम्मार इंडिया लिमिटेड के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पुलिस जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह विवाद सिनर्जी फिनहब एलएलपी और एम्मार इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त विकास समझौते (जेडीए) से जुड़ा है। शिकायतकर्ता कंपनी सिनर्जी फिनहब का आरोप है कि एम्मार इंडिया ने करीब 18 एकड़ जमीन की परियोजना से जुड़े पुराने समझौतों और तीसरे पक्ष के दावों को छिपाकर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया। एम्मार की सहायक कंपनियों जय प्रापबिल्ड और रुद्राक्ष रियल्टर्स ने इस जमीन को लेकर तेजस होम बिल्ड और नैनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों के साथ 2010 और 2013 में पहले ही समझौते कर रखे थे, जिन्हें आखिर तक छिपाकर रखा गया है। इन समझौतों की जानकारी सिनर्जी फिनहब को नहीं दी गई, जिस कारण उन्हें बाद में तीसरे पक्ष के दावों का सामना करना पड़ा। नतीजतन कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता को विवाद सुलझाने के लिए अलग से एक करोड़ रुपये का भुगतान और विकसित यूनिट्स का आवंटन भी करना पड़ा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस मनदीप पन्नू की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि यह विवाद एक अनुबंध से उपजा है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी और छल के तत्व मौजूद हैं, जिनसे बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता। सिनर्जी फिनहब ने इस प्रोजेक्ट में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का निवेश किया था। हाई कोर्ट ने निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर मामले का हवाला देते हुए कहा कि सिविल और आपराधिक कार्यवाही साथ-साथ चल सकती है, यदि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, तो जांच को रोका नहीं जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस केस में पाया कि तेजस और नैनी इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ पुराने समझौतों को नहीं बताना अथवा छिपाकर रखना केवल अनुबंध का उल्लंघन नहीं, बल्कि धोखाधड़ी और कपटपूर्ण प्रलोभन का मामला बनता है।

मुश्किलें बढ़ी

- समझौते में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया है तो उसे सिविल विवाद मानकर खारिज नहीं कर सकते

इन कारणों से रद्द नहीं हो सकती एफआइआरः कोर्ट

हाई कोर्ट ने गुरुग्राम की अदालत की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा चूंकि दोनों पक्ष समझौते को लागू कराने के लिए मध्यस्थता में हैं, इसलिए इसे फर्जी नहीं कहा जा सकता। हालांकि, इस एक त्रुटि के कारण पूरी एफआइआर रद्द नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने गुरुग्राम की अदालत द्वारा 10 मार्च 2026 को दिए गए उस आदेश को उचित ठहराया, जिसमें पुलिस को एम्मार इंडिया और उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस गुरुग्राम में दर्ज एफआइआर नंबर 66/2026 के तहत अब जांच जारी रहेगी।

समझौते में हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का उल्लंघन

एम्मार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत दायर की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी (318), जबरन वसूली (308), आपराधिक साजिश (61), धारा 343 और धारा 3 (5) जैसी धाराओं के तहत सिनर्जी फिनहब एलएलपी की ओर से गुरुग्राम के थाने में दर्ज कराए गए केस को चुनौती दी गई थी। सिनर्जी फिनहब का आरोप है कि एम्मार इंडिया ने जानबूझकर पूर्व में बेची हुई जमीन का सौदा किया, तथ्यों को छिपाया और बाद में करोड़ों रुपये हड़पने की नीयत से उसे पंजीकृत प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। एफआइआर में आरोप है कि कंपनी ने बाद में करीब 120 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की। इस पूरे मामले का गंभीर पहलू यह है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले भी गुरुग्राम के सेक्टर 83 में एम्मार पाम गार्डंस में विवादित जमीन बेचने का मामला सामने आया था।

लोकभवन राज्य की प्रशासनिक गरिमा का प्रतीकः राज्यपाल पटेल

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भोपाल स्थित लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक- 2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का बुधवार को लोकार्पण किया। उन्होंने भारत माता के जयघोष के साथ फीता खोलकर प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि लोकभवन प्रदेश की प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक है। प्रवेश द्वारों का सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होना सुरक्षा के साथ ही राज्य की सांस्कृतिक स्थापत्य पहचान को भी सशक्त करता है। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप गेट निर्माण के लिए संबंधित विभागों की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक- 1 एवं 2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पूर्णता तक लगभग 98 लाख 65 हजार रुपयों की लागत आई है। प्रवेश द्वारों की संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए गए हैं, जिससे लोकभवन परिसर का स्वरूप और अधिक आकर्षक, सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ है। राज्यपाल पटेल ने अप्रैल 2025 में लोकभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक- 1 एवं 2 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि-पूजन किया था। उन्होंने पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी थी।

सुदृढ़ीकृत

- राज्यपाल पटेल ने सुदृढ़ीकृत नवनिर्मित प्रवेश द्वार का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री निवास में होगी बहनों की पंचायतः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अपने जन्म दिवस पर बहनों की पाती-भैया के नाम लेकर भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंची बहनों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति बहनों की पाती-भैया के नाम एक आत्मीय पहल है। बहनों का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होता रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की बहनों ने अपने मन के भाव, अनुभव और सुझाव पाती के माध्यम से व्यक्त किए हैं। बहनों ने अपने भैया के प्रति विश्वास, स्नेह और सम्मान को शब्दों में पिरोया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में जल्द ही बहनों से संवाद के लिए विशेष पंचायत आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में गरीब, युवा, नारी और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश में बहनों के कल्याण का कार्य मिशन मोड में चल रहा है। राज्य सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए एक लाख करोड़ रूपए से अधिक के बजट का प्रावधान किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब हमारी बहनें कारखानों और उद्योगों में भी नेतृत्व कर रही हैं। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पहुंची बहनों से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी को अधिक से अधिक प्रसारित करने में सहयोग का आव्हान किया।

संवाद

- प्रधानमंत्री मोदी देश में गरीब, युवा, नारी और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे

प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सोरेन को रामनवमी उत्सव के लिए किया आमंत्रित

टीम एक्शन इंडिया

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तपोवन मंदिर, निवारनपुर के महंत ओम प्रकाश शरण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में मंदिर समिति के सदस्य प्रणय कुमार वर्मा, अयोध्या दास एवं आशुतोष दास शामिल थे।

न एनआरसी होने दूंगी, न डिटेंशन कैंप बनने दूंगीः ममता

केंद्र पर हमला

- केंद्र की एजेंसियों, केंद्रीय बलों को भी संदेश देते हुए कहा कि वे निष्पक्ष होकर कर्तव्य निभाएं

टीम एक्शन इंडिया

जलपाईगुड़ी। उत्तर बंगाल से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरूआत तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को जिले के मयनागुड़ी टाउन क्लब मैदान से की। इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार राममोहन राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरूआत विकास कार्यों की समीक्षा से की। उन्होंने बताया कि 11 करोड़ रुपये में सड़क निर्माण हो रहा है, महाकाल मंदिर का निर्माण जारी है और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक हिंसक पार्टी है। उनके भाषण में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का डर, मूल्यवृद्धि, जनजातीय भावनाएं और पहचान पत्र विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची (एसआईआर) को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि राजबंशी समुदाय तथा महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र की एजेंसियों और केंद्रीय बलों को भी संदेश देते हुए कहा कि वे निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभाएं। एनआरसी पर चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे रहते बंगाल में एनआरसी करके डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। भाजपा संविधान या लोकतंत्र की परवाह नहीं करती है। अकाल बारिश में आलू किसानों को राहत का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार उनके साथ है।

माता कौशल्या महोत्सव 2026 का मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने किया शुभारंभ

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः जिले के आरंग विकासखंड अंतर्गत चंदखुरी ग्राम में माता कौशल्या महोत्सव 2026 का शुभारंभ कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मानस मंडली एवं सुप्रसिद्ध कलाकार पूनम विराट तिवारी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने संबोधित करते हुए कहा कि यह महोत्सव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी कर महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रभु श्रीराम के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में 500 वर्षों बाद भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं। छत्तीसगढ़ सरकार उनके बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं। मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में संचालित रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी है तथा महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मंत्री ने आगे कहा कि सभी के सहयोग से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाया जाएगा। साथ ही नवा रायपुर में फिल्म सिटी, मेडिसिटी सहित विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। माता कौशल्या महोत्सव न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपरा और पहचान को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण मंच भी है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से जहां एक ओर श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूती मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है।

महतारी वंदन

- यह महोत्सव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आयोजित किया जा रहा है

राज्यपाल से यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता ने की भेंट

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से बुधवार को लोकभवन में यूनीसेफ के इमेजिन वेंचर के प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता एवं एलियन इनोवेशन्स हैदराबाद के संस्थापक रवि किरण ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विकसित नवीनतम सहायक उपकरण का प्रदर्शन किया और इसकी विशेषताओं की जानकारी दी। रवि किरण ने बताया कि यह उपकरण दृष्टिबाधित लोगों को दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेगा। भेंट के दौरान उन्होंने राज्य में दृष्टिबाधितजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आगामी लॉन्च कार्यक्रम के लिए राज्यपाल को आमंत्रित भी किया। राज्यपाल ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर एलियन इनोवेशन्स की प्रमुख सुश्री हर्षिता भी उपस्थित थी।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने श्री देव सुमन विवि के विकसित प्रज्ञानम् एआई चैटबॉट का किया लोकार्पण

टीम एक्शन इंडिया

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को लोक भवन में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विकसित प्रज्ञानम्-एआई चैटबॉट का लोकार्पण किया। यह चैटबॉट विशेष रूप से वेद, उपनिषद, पुराण, प्राचीन भारतीय गणित, नाट्यशास्त्र, संगीत, आयुर्वेद, दर्शन एवं भारतीय विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित विस्तृत डेटाबेस पर निर्मित है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा वेद, पुराण उपनिषद और प्राचीन सभ्यता में निहित ज्ञान आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रज्ञानम् जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस अमूल्य ज्ञान को 21वीं सदी की आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह चैटबॉट न केवल जिज्ञासाओं का समाधान करेगा, बल्कि शोध आधारित और प्रमाणिक जानकारी देकर उपयोगकताओं को भारतीय ज्ञान की गहराई से परिचित कराएगा। राज्यपाल ने इस परियोजना के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह चैटबॉट एक वर्ष के गहन शोध का परिणाम है। इस दौरान भारतीय ज्ञान प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए तथा दो पुस्तकों का भी निर्माण किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित कर व्यापक विमर्श किया गया, जिससे इस परियोजना को मजबूत आधार मिला। राज्यपाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तकनीक के साथ अधिक जुड़ी हुई है, ऐसे में प्रज्ञानम् उन्हें अपनी जड़ों, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से इस पहल के ब्रांड एंबेसडर बनने का आान करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की इस ज्ञान पहल को वैश्विक स्तर तक पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकार्पण कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय को बधाई देते हुए कहा कि देश-विदेश के विद्यार्थी, शोधकर्ता और सामान्य लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को डिजिटल माध्यम से आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके जोशी ने प्रज्ञानम् चैटबॉट का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और इसकी कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता के बारे में जानकारी साझा की। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन, विधि परामर्शी कौशल किशोर शुक्ल, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. परविंदर कौशल, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमाकांत पाण्डेय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी, स्वामी जगन्नाथ आश्रम ऋषिकेश के महंत लोकेश दास, गरीबदासी आश्रम हरिद्वार के स्वामी रविदेव शास्त्री महाराज, चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार के स्वामी शिवानंद महाराज, स्वामी नारायण आश्रम ऋषिकेश के स्वामी नारायण चरण दास महाराज, निर्मल संतपुरा आश्रम हरिद्वार के महंत जगजीत सिंह महाराज, कृष्ण कुंज आश्रम ऋषिकेश के स्वामी गोपालाचार्य महाराज, रामनिवास आश्रम हरिद्वार के स्वामी दिनेश दास महाराज, स्वामी सुतीक्ष्ण मुनि महाराज आदि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञानम्-एआई चैटबॉट भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह चैटबॉट भारतीय ज्ञान प्रणाली से जुड़े विषयों पर जिज्ञासुओं के प्रश्नों का त्वरित, सटीक एवं संदर्भ आधारित उत्तर प्रदान करने में सक्षम है। इसे विश्वविद्यालय द्वारा वन यूनिवर्सिटी-वन रिसर्च पहल के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा पर किए गए शोध कार्यों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत विषयवस्तु के आधार पर विकसित किया गया है।

विस्तृत डेटाबेस

- यह चैटबॉट विशेष रूप से वेद, उपनिषद, पुराण, भारतीय गणित, भारतीय विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित विस्तृत डेटाबेस पर निर्मित

बजट चर्चा में पक्ष-विपक्ष आमने-सामने, एकल नारी से लेकर भ्रष्टाचार तक उठे मुद्दे

मांग

» एकल नारी महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की मांग

पंकज शर्मा

शिमला। प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान बुधवार को विभिन्न मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने बजट को संतुलित और समावेशी बताया, वहीं विपक्ष ने कई खामियों को उजागर किया।

मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने आपदा के दौरान सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद से महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में लगातार वृद्धि की गई है। इस बार आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार एकल नारी महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं लाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

सत्ती ने उठाए भ्रष्टाचार के मुद्दे

भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में हजारों ऑफलाइन टेंडर जारी किए गए, जिनमें छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी बड़े खर्च दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई वर्षों से ऑटो चालकों को परमिट नहीं मिल रहे हैं और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है। सत्ती ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है।

कानून व्यवस्था और नीतियों पर विपक्ष का सवाल

सत्ती ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है और भू-माफिया सक्रिय है। उन्होंने धारा 118 से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें जांच को दबाया गया। साथ ही उन्होंने विधायक निधि में कटौती का विरोध किया और किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया।

कमलेश ठाकुर का पहला संबोधन चर्चा में रहा

देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर ने पहली बार विधानसभा में अपनी बात रखते हुए बजट को आम लोगों से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी वर्गों–महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों–को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का समर्थन किया और कहा कि इससे घरेलू महिलाओं, किसानों और छोटे स्वरोजगार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने एलपीजी, मनरेगा और आरडीजी की स्थिति को वेंटिलेटर पर बताते हुए केंद्र और राज्य के समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि कोई भी बजट पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और विपक्ष का काम कमियों को सामने लाना है। उन्होंने प्रदेश की आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने की जरूरत बताई।

सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शहीद नमांश स्याल को भी किया नमन

टीम एक्शन इंडिया

हमीरपुर। भारतीय वायु सेना की एरोबेटिक टीम में सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के पासआउट विद्यार्थी भी शामिल हैं। 25-26 मार्च को सुजानपुर में आयोजित किए जा रहे एयर शो में इसी स्कूल के 10वें बैच के विद्यार्थी रहे और वर्तमान में एयर फोर्स स्टेशन आदमपुर (पंजाब) के प्रभारी एयर कमोडोर बृजेश पॉल और स्क्वॉड्रन लीडर हिमकुश चंदेल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एयर शो के प्रथम दिन की समाप्ति से पहले एरोबेटिक टीम ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के सम्मान में आकाश में एक विशेष फॉर्मेशन बनाकर उन्हें नमन किया। कांगड़ा जिले के नगरोटा क्षेत्र के शहीद विंग कमांडर स्याल भी सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के विद्यार्थी थे और उन्हें भारतीय वायु सेना के बेहतरीन पायलटों में गिना जाता था।

विधानसभा प्रश्नकाल

प्रश्नकाल में गूंजा टोल टैक्स मुद्दा, सीमावर्ती लोगों को राहत पर सरकार का संकेत

पंकज शर्मा

शिमला। प्रदेश विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान टोल टैक्स का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के ऐसे लोग जो रोजाना आवागमन करते हैं, उन्हें पास जारी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा।

उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग नियमित रूप से प्रदेश में आते-जाते हैं, वे अपने वाहनों का पंजीकरण हिमाचल में करवा लें, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल की टैक्सियों और एमएमवी पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, वहीं प्रदेश की निजी गाड़ियों को भी टोल से छूट है। बाहर से आने वाले वाहनों पर ही यह शुल्क लागू है।

यह जानकारी उन्होंने विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी और राकेश कालिया के सवालों के जवाब में दी, जबकि रणधीर शर्मा ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे। मुख्यमंत्री ने बताया कि टोल बैरियर के ऑक्शन के लिए आरक्षित राशि 185 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन यह 228 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ।

एनएचएआई और राज्य के टोल बैरियर एक ही स्थान पर होने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थानों पर दोनों को एकीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही टोल प्रणाली को फास्टैग से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि टोल टैक्स में उतनी वृद्धि नहीं की गई है, जितना इसका विरोध किया जा रहा है। विधायकों ने सीमावर्ती गांवों के लोगों को राहत देने की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

प्रवेश शुल्क से बढ़ेगा राजस्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवेश शुल्क में वृद्धि से सरकार को लगभग 228 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 54 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन अभी संभव नहीं है, लेकिन आम उपभोक्ताओं पर इसका असर नगण्य रहेगा।

स्थानीय लोगों को टोल में राहत

सरकार की टोल नीति के तहत तिमाही और वार्षिक दरें केवल उन वाहन मालिकों पर लागू होंगी, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और किसी टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसके लिए संबंधित एसडीएम या तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इंदौरा में इंडोर स्टेडियम निर्माण की तैयारी

आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बताया कि इंदौरा क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम कम ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

विदेश दौरे पर 2.04 करोड़ खर्च

उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि जापान, हांगकांग और वियतनाम के दौरे पर लगभग 2.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह दौरा केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत था और इसका उद्देश्य सीधे निवेश लाना नहीं था।

उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 2411 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जबकि 88 बंद हुई हैं। एमएसएमई के तहत प्रदेश को 105 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 5 करोड़ एक्सपोजर विजिट के लिए थे।

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत शिमला में एमएसएमई फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए और 2500 करोड़ के निवेश को सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिल चुकी है।

अटल आदर्श स्कूल बंद नहीं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अटल आदर्श विद्यालयों को बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। साथ ही राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की जा रही है।

कूड़ा प्रबंधन बना चुनौती

विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के शहरी निकायों में कूड़ा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। खासकर 16 नवगठित नगर निकायों में कूड़ा संग्रहण और निपटान की व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

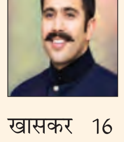

प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई गणना को पूरा करने पर हिमाचल सम्मानित

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग को सिंचाई गणना 2023द्2025 के अंतर्गत पहली बार प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई (एमएमआई) गणना सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने सचिव जल शक्ति विभाग डॉ. अभिषेक जैन को प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति सचिव वी.एल. कंथा राव भी उपस्थिति थे। मुख्य सचिव संजय गुप्ता और सचिव जल शक्ति डॉ. अभिषेक जैन ने आज शिमला में यह पुरस्कार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सिंचाई परियोजनाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत है। सरकार के प्रयासों की झलक वर्ष 2026द्27 के बजट में प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विभाग की डेटा-आधारित योजना, बेहतर शासन और सिंचाई क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एमएमआई गणना का उद्देश्य सिंचाई से संबंधित आंकड़ों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटा-बेस तैयार करना हैं। इसके अंतर्गत जिन सिंचाई परियोजनाओं का सिंचित कमांड क्षेत्र (सीसीए) 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता हैं, उन्हें प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की परियोजनाओं को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है।

सनोली में सट्टा खेलते युवक पकड़ा, नकदी व पर्ची बरामद

राजन पुरी

ऊना। सदर थाना ऊना के तहत सनोली में पुलिस ने सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी और सट्टा पर्चियां बरामद की हैं। जानकारी के मुताबिक गत रात्रि पुलिस चौकी संतोषगढ़ के प्रभारी एसआई राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सनोली क्षेत्र में दबिश दी। इस दौरान आरोपी गगनदीप निवासी संतोषगढ़ को सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया।

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1240 रुपये की नकदी और दड़ा-सट्टा की पर्चियां बरामद कीं। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

हजारों लोगों ने देखा भारतीय वायु सेना का अद्भुत शौर्य

टीम एक्शन इंडिया

सुजानपुर। भारतीय वायु सेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा बुधवार को सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के मैदान के ऊपर किए गए एयर शो के दौरान हजारों लोगों ने इस टीम के बेहतरीन अधिकारियों एवं पायलटों के अदभुत शौर्य, कौशल और आपसी समन्वय का एक हैरतअंगेज प्रदर्शन देखा।

हिमाचल प्रदेश में पहली बार किए जा रहे इस एयर शो के साक्षी बनकर सभी दर्शक अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक एमके-132 जेट विमानों ने करीब 10:50 बजे एक साथ सुजानपुर के आसमान में दस्तक दी तो हजारों लोगों ने जोरदार तालियों के साथ भारतीय वायु सेना के इन जांबाजों का स्वागत किया।

इसके बाद इन विमानों ने अलग-अलग और ग्रुप में एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कलाबाजियां और करतब दिखा कर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया।

गर्जना के साथ आसमान को चीरते हुए इन विमानों ने कई फॉर्मेशन्स बनाकर रोमांच, गति, नियंत्रण और आपसी समन्वय का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। नौ विमानों के इस समूह ने हवा में डायमंड, तीर, हृदय, डीएनए और कई अन्य आकृतियां बनाने के साथ-साथ जब आसमान में राष्ट्रीय ध्वज के रंग बिखेरे तो दर्शकों को एक बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिला। इन अदभुत दृश्यों को देखकर सभी दर्शक इन्हें अपने-अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैप्चर करने से अपने आपको रोक नहीं सके।

बंगाणा में 29 मार्च को लगेगा विशाल मेगा नि:शुल्क चिकित्सा कैंप

राजन पुरी

ऊना। कुटलैहड़ क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कुटलैहड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक दविंदर भुट्टो की ओर से 29 मार्च को होटल कर्ण राज बंगाणा में एक विशाल नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह चिकित्सा शिविर सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा पीजीआई एमईआर एवं 32 मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

पूर्व विधायक भुट्टो ने बताया कि इस चिकित्सा शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि कई बार आर्थिक तंगी और दूरी के कारण लोग बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस तरह के नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। भुट्टो ने बताया कि इस शिविर में पीजीआईएमईआर एवं 32 मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ के अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर विभिन्न रोगों की जांच और परामर्श प्रदान करेंगे। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे।

सौहार्द, सामंजस्य तथा सदस्यों के सहयोग से चलता है सदन : कुलदीप सिंह पठानियां

चमन शर्मा

शिमला। बजट सत्र चरण –॥ के सातवें दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घण्डल, हि0प्र0 विश्वविद्यालय विधि विभाग तथा ऑकलैंड हाऊस स्कूल लक्कड़ बाजार शिमला के 150 छात्र ङ्क छात्राओं ने आज विधान सभा की कार्यवाही देखने से पूर्व हि0प्र0 विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से कौंसिल चैम्बर के गेट नं0 1 पर मुलाकात की। छात्रों ने विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से सदन की कार्यवाही, विधान सभा की कार्यप्रणाली स्पीकर की सदन में भूमिका, विधान सभा का गठन, मन्त्रिपरिषद के गठन सम्बन्धी कई प्रश्न पूछे जिसका उन्होने सिलसिलेवार जवाब भी दिया। संवाद के दौरान उन्होने कहा कि हमारी संसदीय व्यवस्था संघीय ढाँचे पर आधारित है जो केन्द्र व राज्य के रूप में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर व्यवस्था के अनुरूप बनती है।

केन्द्र में संसद है जिसमें ऊपरी सदन राज्य सभा तथा निचला सदन लोक सभा है जबकि राज्यों में विधान परिषद तथा विधान मण्डल हैं। विधान परिषद का प्रावधान सिर्फ बड़े राज्यों में है। पठानियां ने कहा कि वह चौदहवीं विधान सभा के सर्वसम्मति से निर्वाचित अध्यक्ष हैं। उनका प्रमुख कार्य विधान सभा की कार्यवाही का संचालन करना होता है जिसके लिए वह सत्ता पक्ष तथा प्रति पक्ष दोनों का सहयोग लेते हैं ताकि सदन की कार्यवाही निर्विघ्न चलती रहे। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों की ओर इशारा करते हुए पठानियां ने कहा कि आप आने वाले अधिवक्ता तथा न्यायधीश हैं। आप देश के भविष्य हैं तथा इस देश की आजादी लोकतांत्रिक प्रणाली तथा कानून व्यवस्था को उच्च स्तर पर रखना आप सभी की जिम्मेवारी है। पठानियां ने संवाद के दौरान कहा कि देश आजाद कराने में जिन स्वतंत्रता सैनानियों ने अपनी भूमिका निभाई है वह अधिकतर बैरिस्टर थे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को मिले सीधा फंड : जगजीत

राजन पुरी

ऊना। जिला ऊना में स्कूलों में खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से डीपीई एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग से स्कूलों को सीधे फंड देने की मांग तेज कर दी है। बुधवार को जारी संयुक्त प्रेस ब्यान में एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह एवं महासचिव भूपिंदर सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले की तरह स्कूलों को सीधे फंड प्रदान किए जाए, ताकि वे अपनी आवश्यकता और खेल गतिविधियों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की खेल सामग्री खरीद सकें और विद्यार्थी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

जगजीत सिंह कहा कि पूर्व में प्रत्येक स्कूल को लगभग 25,000 रूपये का अनुदान दिया जाता था, जिससे स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार उपयुक्त और बेहतर गुणवत्ता का सामान खरीद पाते थे।

तीन नए सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए एमओयू हस्ताक्षरित

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। प्रदेश में तीन नए सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकारण (हिमुडा) और हाउसिंग एंड अर्बन डिवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच आज यहां नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया।

इस एमओयू के अंतर्गत हिम चंडीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली एयरोसिटी का निर्माण किया जाएगा। हिमुडा की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव डॉ. सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ तथा हुडको की ओर से क्षेत्रीय प्रमुख नीरज सेठी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर राजेश धर्माणी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने में यह परियोजनाएं मील पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में बढ़ते शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को योजनाबद्ध, सतत् विकास के दृष्टिगत भविष्य के अनुरूप शहरी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की नियोजित शहरीकरण की परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि में यह परियोजनाएं सहायक साबित होंगी। यह पहल नए आर्थिक अवसरों के सृजन में सहायक होगी। इन परियोजनाओं के साकार होने से प्रदेश को एक नई पहचान और लोगों को रोज़गार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अवसर मिलेंगे।

इस अवसर पर हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, हिमुडा और हुडको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, अधिकारियों को दी बधाई

टीम एक्शन इंडिया

सुजानपुर। एयर शो के आयोजन के लिए कैप्टन रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया तथा वायु सेना, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा और प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह के एयर शो की मेजबानी का मिलना सुजानपुर के लिए एक गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने इसके सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को वायु सेना और सैनिक स्कूल के अधिकारियों का सहयोग करने तथा सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए थे।

कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपने शौर्य एवं देशभक्ति की उच्च परंपराओं के लिए जानी जाती हैं और इनमें हिमाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इस शो के माध्यम से प्रदेश के युवा प्रेरित एवं प्रोत्साहित होंगे।

टकोली स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षकों व पूर्व सैनिकों का मिला सम्मान

राजन पुरी

ऊना। समाज में सेवानिवृत्त शिक्षकों और पूर्व सैनिकों की भूमिका को सशक्त बनाने तथा उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजकीय प्राथमिक पाठशाला टकोली में राष्ट्र के निर्माता और राष्ट्र के रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उनके बहुमूल्य अनुभवों को समाज तक पहुंचाना और उन्हें नई ऊर्जा के साथ समाज सेवा के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में एलिमेंट्री उपनिदेशक ऊना सोम लाल धीमान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ बीईईओ जोल अश्मील मोहम्मद तथा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड जोल के अध्यक्ष विजय पटियाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उपनिदेशक सोम लाल धीमान ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक और सेना के पूर्व अधिकारी समाज की अमूल्य धरोहर हैं।

चायल - कोटी कॉलेज में वार्षिक समारोह पर नवाजे मेधावी

चमन शर्मा

शिमला। डिग्री कॉलेज चायल – कोटी में बुधवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया । एस0जे0वी0एन0एल0 के चीफ जनरल मैनेजर बलजीत ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जबकि सीनियर मैनेजर (एच.आर.) आशीष नेगी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना से किया। तदोंपरांत विद्यार्थियों ने हिमाचली गिद्दा, वेस्टर्न डांस, पहाड़ी नाटी आदि प्रस्तुतियां देकर समां बांधा।

मुख्य अतिथि बलजीत ने अपने संबोधन में समारोह की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने और उन गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया जो उनके स्वयं एवं देश के विकास के लिए हितकारी हो। महाविद्यालय के लिए एवं शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु एस. जे. वी. एन. एल. से जितनी सहायता संभव होगी सदैव की जाएगी। इस मौके पर उन्होने अकादमिक, छात्र परिषद्, पत्रिका संपादक, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि में भाग लेने एवं विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

इससे पहले प्राचार्य डॉ. दीपशिखा भारद्वाज द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की ओर अतिथियों एवं विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान बलदेव पूरी ज, पी.टी.ए. प्रधान रामकृष्ण शर्मा एवं अभिभाव तथा कॉलेज के शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग मौजूद रहे।